

विहंगावलोकन
**मानव विकास
रिपोर्ट 2016**



हर एक के लिए मानव विकास



मानव विकास रिपोर्ट 2016 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) द्वारा प्रकाशित वैश्विक मानव विकास रिपोर्टों की श्रृंखला में नवीनतम प्रस्तुति है। यू.एन.डी.पी. विकास से जुड़े मुद्दों, रुझानों और नीतियों की स्वतंत्र, विश्लेषणात्मक और अनुभवसिद्ध चर्चाओं के रूप में 1990 से ही इन रिपोर्टों का प्रकाशन करता आ रहा है।

मानव विकास रिपोर्ट 2016 से संबंधित अतिरिक्त जानकारियाँ ऑनलाइन www.hdr.undp.org पर देखी जा सकती हैं। इनमें रिपोर्ट की डिजिटल प्रतियाँ और विहंगमलोकन के 20 से अधिक भाषाओं में अनुवाद, रिपोर्ट का एक संवादात्मक वेब संस्करण, रिपोर्ट के लिए जुटाए गए पृष्ठभूमि लेखों और विचार लेखों का संग्रह, मानव विकास सूचकांकों के संवादात्मक मानचित्र और डाटाबेस, रिपोर्ट के साथ लगे सूचीपत्रों में प्रयुक्त स्रोतों और पद्धतियों के पूर्ण स्पष्टीकरण, देशों की प्रोफाइल और अन्य पृष्ठभूमि सामग्री तथा साथ ही पिछली वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्टें शामिल हैं। 2016 रिपोर्ट और मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय की श्रेष्ठतम विषय सामग्री, जिनमें प्रकाशन, डाटा, एच.डी.आई. श्रेणियाँ तथा संबंधित जानकारी एक नए और उपयोग में आसान मोबाइल ऐप के माध्यम से एपल आईओएस और एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर भी देखी जा सकती हैं।



आवरण इस मूल संदेश को प्रतिबिंबित करता है कि मानव विकास हर एक के लिए है। मानव विकास की यात्रा में किसी को भी नहीं छोड़ा जा सकता। अमूर्त शैली का प्रयोग करते हुए आवरण तीन बुनियादी बातें संप्रेषित करता है। पहली, नीले और सफेद में ऊपर की ओर उठती लहरें आगे के उस रास्ते की द्योतक हैं जो सार्वभौम मानव विकास सुनिश्चित करने के लिए मानवजाति को तय करना है। लहरों के भिन्न-भिन्न मोड़ हमें सचेत करते हैं कि कुछ मार्ग अधिक कठिन होंगे और इन मार्गों पर चलना आसान नहीं होगा, किंतु बहुत-से विकल्प खुले हुए हैं। दूसरे, इस यात्रा में कुछ लोग आगे निकल जाएंगे, किंतु लोग पिछड़ जाएंगे। जो लोग पिछड़ जाएंगे उन्हें आगे निकल गए लोगों के सहायता के लिए बड़े हुए हाथों की जरूरत होगी। दो हाथों की मुद्राएं मानव एकजुटता की इसी भावना को प्रतिबिंबित करती हैं। तीसरा, हरा और नीला – ये दो रंग और शिखर पर हाथ बताते हैं कि सार्वभौम मानव विकास के लिए पृथ्वी, शांति और लोगों के बीच संतुलन की आवश्यकता है।

कॉपीराइट © 2016

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा
1 यू.एन. प्लाजा, न्यू यॉर्क, एन.वाई. 10017 यू.एस.ए.

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन का कोई भी भाग पूर्वानुमति लिए बिना किसी भी रूप में अथवा इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोप्रतिलिपि बनाने, रिकॉर्ड करने या किसी भी अन्य तरीके से पुनःप्रकाशित, प्रसारित और पुनः प्राप्त कर सकने योग्य प्रणाली में संचित नहीं किया जा सकता।

संपादन और प्रकाशन : कम्प्यूनिकेशंस डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेटेड, वाशिंगटन डीसी, यू.एस.ए.

सूचना डिजाइन और डाटा अभिकल्पना : क्युइन इंफॉर्मेशन डिजाइन और मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय
आवरण अभिकल्पना : फोनिकस डिजाइन एड

हिन्दी अनुवाद : याशियान लेंगुएज सर्विसेज, नई दिल्ली, भारत

मुद्रण के बाद पाई गई किन्हीं भी त्रुटियों और भूल-चूकों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर <http://hdr.undp.org> पर जाएं

विहंगावलोकन
मानव विकास रिपोर्ट 2016

हर एक के लिए मानव विकास



*Empowered lives.
Resilient nations.*

संयुक्त राष्ट्र विकास
कार्यक्रम (यूएनडीपी)
के लिए प्रकाशित

मानव विकास रिपोर्ट 2016 टीम

निदेशक और अग्रणी लेखक
सलीम जहां

उप निदेशक
इवा जेसपर्सन

अनुसंधान और सांख्यिकी

शांतनु मुखर्जी (टीम प्रमुख), मिलोरद कोवासेविक (प्रधान सांख्यिकीकार), बोटागोज अब्देयेवा, एस्ट्रा बोनिनी, सिसीलिया काल्देरॉन, क्रिस्टेले काजाबत, यू-ची सू, क्रिस्टीना लेंगफेलदर, पैट्रीजिया लुऑंगो, तन्नी मुखोपाध्याय, शिवानी नय्यर और हेरिबरतो तापिया

प्रकाशन और वेब

एडमिर जाहिक और धार्शनी सेनेविरत्ने

संपर्क और संचार

जोन हॉल, सासा लूसिक, जेनिफर ओ'नील ओल्डफील्ड और अन्ना अर्तुबिया

कार्य और प्रशासन

सरंतूया मैड (ऑपरेशंस मैनेजर), फे हुआरेज शनाहन और मे विंट थान



प्राक्कथन

मानव विकास का कुल निचोड़ है मानव स्वतंत्रता : प्रत्येक मानव जीवन की, केवल कुछेक की नहीं, न ही अधिकांश की, बल्कि विश्व के हर एक कोने में रह रहे सभी मानव जीवन की पूर्ण क्षमता को साकार करने की स्वतंत्रता – अभी और भविष्य में भी। ऐसा सार्वभौमिकतावाद मानव विकास के दृष्टिकोण को अनूठा बना देता है।

तथापि सार्वभौमिकतावाद का सिद्धांत एक बात है और उसे आचरण में उतारना दूसरी बात। विगत चौथाई सदी में मानव विकास के मोर्चों पर प्रभावशाली प्रगति हुई है। अब लोग अधिक लंबे समय तक जीवित रहते हैं, अधिक लोग चरम गरीबी से ऊपर उठ रहे हैं और कम लोग कुपोषित हैं। मानव विकास ने मानव जीवन को समृद्ध किया है – किंतु दुर्भाग्य से सभी को समान सीमा तक नहीं किया है और उससे भी बुरी बात यह कि प्रत्येक जीवन को समृद्ध नहीं किया है।

यही कारण है कि 2015 में संयोग से नहीं बल्कि सोच-समझकर विश्व नेताओं ने एक ऐसी विकास यात्रा के प्रति स्वयं को वचनबद्ध किया जिसमें कोई भी पीछे न छूटे – एजेंडा 2030 की यह केंद्रीय प्रतिज्ञा है। इस सार्वभौम आकांक्षा को प्रतिबिंबित करते हुए यह सामयिक ही है कि 2016 की मानव विकास रिपोर्ट हर एक के लिए मानव विकास की थीम को समर्पित है।

रिपोर्ट एक व्यापक तस्वीर उकेरने के साथ आरंभ होती है जिसमें विश्व के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों और बेहतर भविष्य के लिए मानवता की आशाओं को दर्शाया गया है। कुछ चुनौतियां लंबे समय से बनी हुई हैं (अभाव और वंचनाएं), कुछ गहरी हो रही हैं (असमानताएं) और कुछ उभर रही हैं (हिंसक उग्रवाद), किंतु अधिकांश एक दूसरे को बल प्रदान कर रही हैं। इन चुनौतियों का स्वरूप और फैलाव चाहे जो हो, वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ियों के लोगों की सकृशलता पर उनका प्रभाव पड़ रहा है।

इसी के साथ रिपोर्ट हमें याद दिलाती है कि मानवता ने विगत 25 वर्षों में कितना कुछ अर्जित किया है और उम्मीद जगाती है कि आगे की प्रगति भी संभव है। हमने जो अर्जित किया है उस पर हम आगे निर्माण कर सकते हैं, चुनौतियों से उबरने के लिए नई संभावनाओं का दोहन कर सकते हैं और जो कभी अप्राप्य समझा जाता था उसे प्राप्त कर सकते हैं। आशाओं को साकार करना हमारी पहुंच के भीतर है।

व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हुए रिपोर्ट फिर दो आधारभूत प्रश्न उठाती है : मानव विकास की प्रगति में कौन-कौन पीछे छूट गया है और यह कैसे और क्यों हुआ। यह इस बात पर बल देती है कि गरीब, दरकिनार और कमजोर समूह – जिनमें जातीय अल्पसंख्यक, मूल देशज लोग, शरणार्थी और प्रवासी भी शामिल हैं – सबसे पीछे छूटते जा रहे हैं। सार्वभौमिकता के अवरोधों में अन्य रुकावटों के अलावा अभाव और असमानताएं, पक्षपात और अपवर्जन, सामाजिक मान्यताएं और मूल्य तथा पूर्वग्रह और

असहिष्णुता शामिल हैं। रिपोर्ट परस्पर बल प्रदान करने वाले उन लैंगिक अवरोधों को भी रेखांकित करती है जो अनेक महिलाओं को उनके जीवन की पूर्ण क्षमता को साकार करने के लिए आवश्यक अवसरों और सशक्तीकरण से वंचित करते हैं।

रिपोर्ट बल देकर कहती है कि हर एक के लिए मानव विकास सुनिश्चित करने के लिए पीछे छूट गए लोगों के अभावों और वंचनाओं के स्वरूप और कारणों की पहचान करना भर काफी नहीं है। मानव विकास की विश्लेषणात्मक रूपरेखा और आकलन परिप्रेक्ष्यों के कुछ पहलुओं को प्रमुखता दी ही जानी चाहिए ताकि उन मुद्दों को संबोधित किया जा सके जो सार्वभौम मानव विकास को रोकते हैं। उदाहरण के लिए, मानव अधिकार और मानव सुरक्षा, वाणी और स्वायत्तता, सामूहिक उत्तरदायित्व और चयनों की अंतर्निर्भरता वर्तमान में पीछे छूट गए लोगों के मानव विकास के लिए कुंजी हैं। इसी प्रकार, मानव विकास के लाभ हर एक तक पहुंचें, इसका आकलन करने और इसे सुनिश्चित करने के लिए मानव विकास परिणामों की केवल मात्रा नहीं अपितु गुणवत्ता पर, औसत तथा अलग-अलग सांख्यिकियों (विशेष रूप से अलग-अलग लैंगिक सांख्यिकियों) से आगे जाने पर विचार अवश्य किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट सशक्त रूप से तर्क प्रस्तुत करती है कि पीछे छूट गए लोगों का ध्यान रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चार सूत्रीय नीति की कार्यनीति अपनाव आवश्यक है : सार्वभौम नीतियों का उपयोग करते हुए पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचना (उदाहरण के लिए, मात्र वृद्धि नहीं, बल्कि समावेशी वृद्धि), विशेष जरूरतों वाले लोगों (उदाहरण के लिए, अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों) के लिए उपाय करते रहना, मानव विकास को लचीला बनाना और छूट गए लोगों को सशक्त बनाना।

रिपोर्ट उचित ही स्वीकार करती है कि राष्ट्रीय नीतियों के अनुपूरक के रूप में वैश्विक स्तर पर कदम उठाने की आवश्यकता है। यह जनादेश, शासन व्यवस्था के ढांचों और वैश्विक संस्थाओं के काम से जुड़े मुद्दों को संबोधित करती है। यह इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान दिलाती है कि यद्यपि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर हम प्रायः गतिरोध में समाप्त होने वाली सरगर्म बहसों के अभ्यस्त हो चुके हैं, किंतु इस समूचे कोलाहल के नीचे भावी पीढ़ियों के लिये सातत्यपूर्ण विश्व सुनिश्चित करने के लिए अनेक वैश्विक चुनौतियों के आरपार सर्वानुमति भी उभरती रही है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, जो हाल ही में प्रभाव में आया है, इसका प्रमाण है। जो कभी अकल्पनीय माना गया था उसे अब रोका न जा सकने योग्य सिद्ध होना ही चाहिए।

सार्वभौमिकतावाद के सिद्धांत को साझा करके और आधारभूत मुद्दों – जैसे अत्यधिक निर्धनता का उन्मूलन

करना, भूख को समाप्त करना – पर ध्यान केंद्रित करके और सातत्यता के मूल मुद्दे को उभारकर यह रिपोर्ट एजेंडा 2030 के अनुपूरक का कार्य करती है। मानव विकास दृष्टिकोण और एजेंडा 2030 एक दूसरे के आख्यानो में योगदान देकर, यह पता लगाकर कि मानव विकास और सतत विकास लक्ष्यों के संकेतक एक दूसरे के अनुपूरक कैसे बन सकते हैं और एक दूसरे के लिए प्रबल समर्थनकारी मंच होकर एक दूसरे को मजबूत बना सकते हैं।

हमारे पास आशान्वित होने का प्रत्येक कारण है कि मानव विकास में कार्याकल्प कर पाना संभव है। आज जो चुनौतियां जान पड़ती हैं कल उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। किसी को भी पीछे नहीं छूटने देने के इस साहसी एजेंडे को हासिल करने के लिए विश्व के पास 15 से भी कम वर्ष हैं। मानव विकास की खाई को भरना उतना ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है जितना भावी पीढ़ियों के लिए

समान, या बल्कि बेहतर, अवसर सुनिश्चित करना है। हर एक मानव जीवन को समृद्ध बनाने के लिए मानव विकास को सतत और सातत्यपूर्ण होना ही होगा ताकि हम एक ऐसा विश्व बना सकें जिसमें सभी लोग शांति और समृद्धि का लाभ उठा सकें।



हेलेन क्लार्क

प्रशासक

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

आभार



2016 की मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय (एच.डी.आर.ओ.) के प्रयासों का प्रतिफल है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष, विश्लेषण और नीतिगत अनुशंसाएं केवल एच.डी.आर.ओ. की ही हैं और इनके लिए यूएनडीपी अथवा उसके कार्यकारी मंडल के किसी भी सदस्य को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव विकास रिपोर्ट को आधिकारिक रूप से "एक स्वतंत्र बौद्धिक रचना" के रूप में मान्यता दी है, जो "विश्व भर में मानव विकास के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन" बन गई है।

हम नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमृत्य सेन के निरंतर प्रेरणास्पद बौद्धिक परामर्श, मार्गदर्शन और विचारों के लिए अत्यधिक ऋणी हैं। एच.डी.आर.ओ. अनेक प्रतिष्ठित लोगों और संस्थाओं का श्रृंखलाबद्ध योगदान प्राप्त करके गौरवान्वित है। इन हस्ताक्षरित योगदानों के लिए प्रोफेसर डैन एरिएली (ड्यूक यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान और व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र के जेम्स बी. ड्यूक प्रोफेसर), कैरोल बेलामी (ग्लोबल कम्यूनिटी एंगेजमेंट ऐंड रिसिलिएंस फंड के गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पूर्व कार्यकारी निदेशक), मिना कनिघंम कैन (निकारागुआई मिस्किटु, देशज लोगों के अधिकारों की कार्यकर्ता और यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इन्डीजिनस इश्यूज की पूर्व अध्यक्ष), ओलाफर ऐलियासन (कलाकार और लिटिल सन के संस्थापक), मेलिंडा गेट्स (बिल ऐंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह-संस्थापक), डॉ. एंजेला मर्केल (संघीय गणराज्य जर्मनी की चांसलर) और हुआन मैनुअल सांतोस (कोलंबिया के राष्ट्रपति और 2016 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता) विशेष सराहना के अधिकारी हैं। राष्ट्रपति सांतोस का लेख प्राप्त करना आसान बनाने के लिए हम मार्टिन सांतिआगो और यूएनडीपी देश कार्यालय के विशेष रूप से आभारी हैं।

इस रिपोर्ट में योगदान देने के लिए हम यहां नीचे अंकित लेखकों की भी सराहना करना चाहेंगे : पॉल आनंद, आयेशा बानू, फ्लैविओ कोमिन, जिओवानी आंद्रेई कोर्निया, जूलियाना मार्टिनेज फ्रेंजोनी, स्टेफैनी ग्रिफिथ-जोन्स, आइरीन खान, पीटर लुनेनबोर्ग, मैनुअल मोन्तीस, सिद्दीकर ओस्मानी, एनरिके पुरुजोटी, रॉबर्ट पॉलिन, डिएगो सांचेज-एनकोकिआ, अनुराधा सेठ, फ्रांसिस स्टीवर्ट और फ्लोरेंसिया टॉर्च।

हम इस रिपोर्ट में विचार लेखों का योगदान देने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी रिसर्च इंस्टिट्यूट के ऑस्कर ए. गोमेज, साचिको जी. कामिदोहजोनी और अको मुतोय क्रॉस सेक्टरल कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ दि लातविया कैबिनेट ऑफ

मिनिस्टर्स के मारा सिमानेय और सिविल सोसायटी संगठन होप एक्सएक्सएल के भी आभारी हैं। यूएनडीपी के दो वैश्विक नीति केंद्रों – वैश्विक विकास भागीदारियों पर एक केंद्र सिओल में और लचीले पारिस्थितिकी तंत्रों तथा मरुस्थलीकरण पर दूसरा नैरोबी में – ने इस रिपोर्ट में विचार लेखों का योगदान दिया है और इसके लिए हम बोलेश होवार्थ और एनी-गरट्राउड जुएपनर का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।

हमें एक लक्ष्यप्रतिष्ठित परामर्श समिति से भी अमूल्य अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ : ओलु अजाकैये, मैग्दालेना सेपुल्वेदा कारमोना, जिओवानी आंद्रेई कोर्निया, डायने एल्सन, हीबा हैंडोउसा, रिचर्ड जॉली, रवि कानबुर, यासुशी कात्सुमा, एला लिवानोवा, जस्टिन यिफु लिन, लेटीसिया मेरिनो, सोलिया मोनसोद, ओनालिना डू सेलोलवाने और फ्रांसीस स्टीवर्ट।

हम सांख्यिकी परामर्श समिति के सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने रिपोर्ट के मानव विकास सूचकांकों की गणना से संबंधित कार्यपद्धतियों और आंकड़ों के चयन पर विशेषज्ञ परामर्श प्रदान किया : लीजा ग्रेस, एस. बर्सांलेस, अल्बीना चुवा, कोएन डेकांक, एनरिको जिओवानीनी, पास्कुअल गर्सटेनफेल्ड, जैनेट गोर्निक, गेराल्ड हैबरकोर्न, हैशन फु, रॉबर्ट किर्कपैट्रिक, जया कृष्णकुमार और मिशेला सईसाना।

रिपोर्ट के समग्र सूचकांक और अन्य सांख्यिकी संसाधन अपने विशिष्ट क्षेत्रों में अग्रणी अंतरराष्ट्रीय आंकड़ा प्रदाताओं की विशेषज्ञता पर निर्भर रहे हैं और हम एच.डी.आर.ओ. के साथ उनके निरंतर सामूहिक सहकार्य के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सटीकता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए गिसेला रोबल्स एगुइलर, सबीना अलकिर, जैक्स चार्मीज, केनेथ हार्टजेन और निकोलस फैसेल तथा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयोग की उनकी टीम के साथ सांख्यिकीय मुद्दों पर चर्चा से सांख्यिकीय विश्लेषण को बहुत लाभ मिला है।

रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान आयोजित विचार-विमर्श अनेक संस्थाओं और व्यक्तियों की उदार सहायता पर निर्भर थे, जिनकी संख्या यहां उल्लेख करने की दृष्टि से बहुत अधिक है (सहभागियों और भागीदारों की सूची 1जजचरुध्दतक.नदकच. वतहध2016-तमचवतजध्ववदेनसजजपवदे पर है)। बहुहितधारकों के साथ औपचारिक विचार-विमर्श अप्रैल और सितंबर 2016 के मध्य जेनेवा, पेरिस, इस्तांबुल, नैरोबी, सिंगापुर और पनामा में आयोजित किए गए। इन विचार-विमर्शों को आयोजित करने के लिए हम जेनेवा के यूएनडीपी कार्यालय, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और यूएनडीपी के क्षेत्रीय सेवा केंद्रों तथा वैश्विक नीति केंद्रों के और विशेष रूप से रेबेका ऐरिआस, मैक्स एवरेस्ट-फिलिप्स, ऐनी गेरट्राउड

जुएनएन. एलेक्स लैफिटन, मारकोस नेटो और मारिया लुइसा सिल्वा के आभारी हैं। बीजिंग, बोन, कोलंबो, ढाका, हेल्सिंकी, लंदन, मनीला, रेक्जाविक और विएना में 2015 की मानव विकास रिपोर्ट के लोकार्पण के दौरान अनौपचारिक विचार-विमर्श भी आयोजित किए गए थे। यूएनडीपी के क्षेत्रीय ब्यूरो और देश कार्यालयों सहित भागीदार संस्थाओं के योगदान, समर्थन और सहायता को अत्यधिक कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया जाता है।

रिपोर्ट के लिए पाठकों के समूह का गठन करने वाले यूएनडीपी के सहयोगियों का विशेष धन्यवाद व्यक्त किया जाता है : मनदीप धालीवाल, प्रिया गजराज, शीला मानी, अयोडेले ओडुसोला, थंगावेल पलानीवेल, सारा पूल, मुनीर ताबेत, क्लैर वान डर वारीन और क्लाउडिया विनय। रिपोर्ट का राजनीतिक परिशीलन पैट्रिक कुलिअर्स, लूसिआना मरमेट और निकोलस रोसेलिनी ने किया और उनके परामर्श को धन्यवादपूर्वक स्वीकार किया जाता है।

मोएज डोरैड, साकिको फुकुदा-पार, टेरी मैककिनले, सरस्वती मेनन, सिद्दीकुर उस्मानी, स्टेफ़ेनो पेटिनाटो और डेविड स्टीवर्ट सहित एच.डी.आर.ओ. के पूर्व सहयोगियों और रिपोर्ट के मित्रों ने कृपापूर्वक एक दिन हमारे साथ बिताया और अपनी अंतर्दृष्टियाँ, विचार और अनुभव हमारे साथ साझा किए, जो अमूल्य हैं।

इसके अतिरिक्त हमें सामाह अब्दुल्लाह, हेल्मुट के. एनहायर, मिशेल ब्रेस्लौर, कोसमास गीता, रोनाल्ड मेंडोजा, यूजीनिया पिजा-लोपेज, जूलिया रावड, डायना सॉयर और ओलिविर श्वांक के साथ रिपोर्ट से संबंधित विषयों पर चर्चाओं और उनके सुझावों का लाभ मिला। हमारी वेबसाइट पर रिपोर्ट से संबंधित विषयों पर

ऑनलाइन सर्वेक्षणों में भाग लेने वाले सर्वसाधारण के सदस्यों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे।

इंटरन के रूप में अनेक प्रतिभावान युवाओं ने रिपोर्ट में योगदान दिया है : एलेन सू, मोहम्मद तैमूर मुस्तफा, आबेदीन रफीक, जेरेमिआज रोजास, प्रेरणा शर्मा, वेइजी तान और डेनिएल हो तान याउ। अपने समर्पण और योगदान के लिए वे मान्यता के अधिकारी हैं।

हम अत्यंत पेशेवर संपादन और प्रकाशन के लिए ब्रुस रॉस-लारसन के नेतृत्व में जोए कैपोनिओ, माइक क्रमप्लर, क्रिस्टोफर ट्रॉट और ऐलैन विल्सन के साथ कम्यूनिकेशंस डेवलपमेंट इनकॉरपोरेटेड के और डिजाइनरों गेरी क्युइन तथा फीनिक्स डिजाइन एंड के भी आभारी हैं।

सबसे बढ़कर, व्यक्तिगत रूप से, हमेशा की तरह मैं यूएनडीपी की प्रशासक हेलेन क्लार्क के नेतृत्व और दूरदृष्टि और साथ ही मानव विकास के उद्देश्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हमारे कार्य के प्रति उनके ठोस समर्थन के लिए उनका अत्यधिक आभारी हूँ। मैं एच.आर.डी.ओ. की समूची टीम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसने समर्पण के साथ एक ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की है जो मानव विकास की प्रगति की और आगे ले जाने के लिए लालायित है।



सलीम जहां
निदेशक

मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय

मानव विकास रिपोर्ट 2016 की विषयसूची

प्राक्कथन

आभार

विहंगावलोकन

अध्याय 1

मानव विकास – उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और आशाएं

उपलब्धियाँ जो हमने अर्जित की हैं

चुनौतियाँ जो हमारे सम्मुख उपस्थित हैं

आशाएं जो हमारे पास हैं

मानव विकास दृष्टिकोण और एजेंडा 2030

अध्याय 2

सार्वभौमिकतावाद – सिद्धांतों से आचरण तक

सार्वभौमिकतावाद की ओर गतिशीलता

औसतों के पार – मानव विकास सूचकांकों के समूह का उपयोग

साधनहीन समूहों पर एक दृष्टि

गतिशील प्रक्रिया के रूप में मानव विकास में अभाव और वंचनाएं

सार्वभौमिकतावाद के अवरोध

अवरोधों को तोड़ना

अध्याय 3

हर एक तक पहुंचना – विश्लेषणात्मक और आकलन से जुड़े मुद्दे

किन पक्षों के विश्लेषण की आवश्यकता है

जांच करना कि मानव विकास की प्रगति हर एक तक पहुंच रही है या नहीं

– आकलन की आवश्यकताएं

अध्याय 4

छूट गए लोगों का ध्यान रखना – राष्ट्रीय नीति विकल्प

सार्वभौम नीतियों के उपयोग से छूट गए लोगों तक पहुंचना

विशेष जरूरतों वाले समूहों को लिए उपाय करते रहना

मानव विकास को लचीला बनाना

पीछे छूट गए लोगों को सशक्त बनाना

निष्कर्ष

अध्याय 5

वैश्विक संस्थाओं का कार्याकल्प

वैश्विक संस्थाओं में संरचनागत चुनौतियाँ

सांस्थानिक सुधार के लिए विकल्प

निष्कर्ष

अध्याय 6

हर एक के लिए मानव विकास – आगे की राह

हर एक के लिए मानव विकास – एक कार्य एजेंडा

हर एक के लिए मानव विकास – भावी टोस कार्य

निष्कर्ष

नोट

संदर्भ

सांख्यिकीय संलग्नक

पाठक मार्गदर्शिका

सांख्यिकीय सारणियाँ

1. मानव विकास सूचकांक और इसके संघटक
2. मानव विकास सूचकांक के रुझान, 1990–2015
3. असमानता–समायोजित मानव विकास सूचकांक
4. लैंगिक विकास सूचकांक
5. लैंगिक असमानता सूचकांक
6. बहुआयामी निर्धनता सूचकांक : विकासशील देश
7. जनसंख्या के रुझान
8. स्वास्थ्य परिणाम
9. शैक्षिक उपलब्धियाँ
10. राष्ट्रीय आय और संसाधनों का संयोजन
11. कार्य और रोजगार
12. मानव सुरक्षा
13. अंतरराष्ट्रीय एकीकरण
14. अनुपूरक संकेतक : सकुशलता की धारणाएं
15. आधारभूत मानव अधिकार संधियों की स्थिति

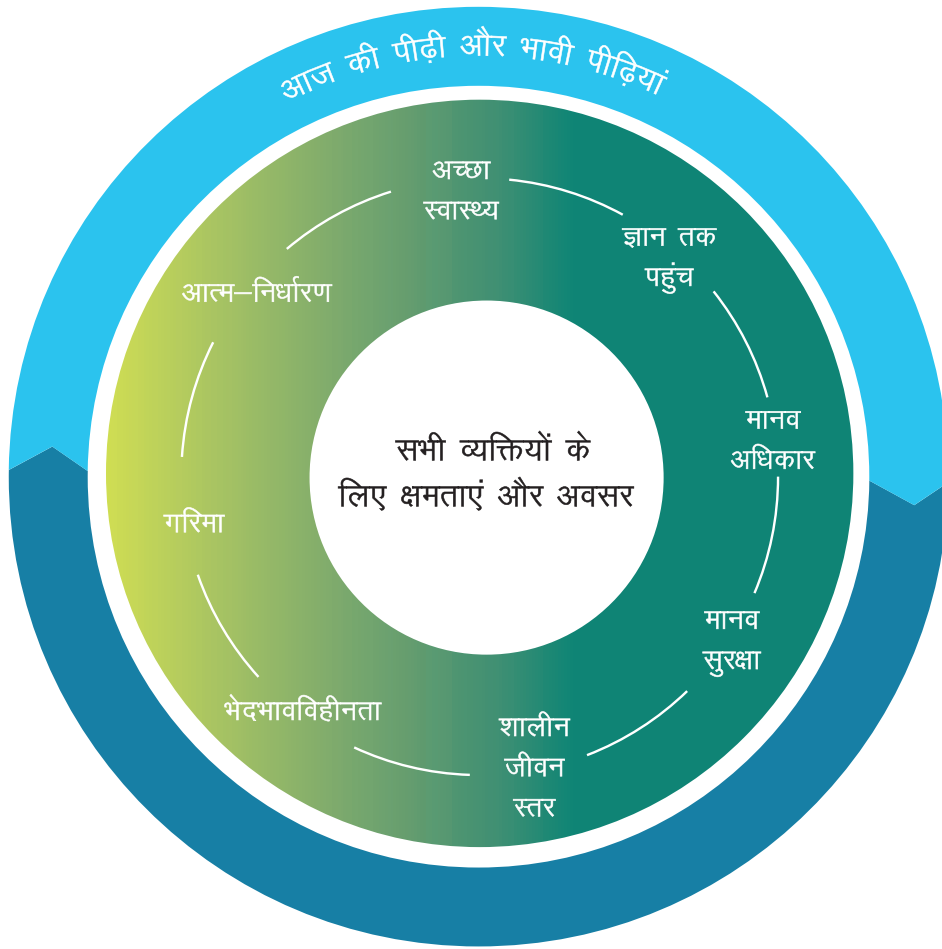
मानव विकास के नियंत्रणपट्ट

1. जीवन–अवधि लैंगिक अंतर
2. सतत विकास

क्षेत्र

सांख्यिकीय संदर्भ

सूचना-रेखांकन 1 हर एक के लिए मानव विकास





विहंगावलोकन

हर एक के लिए मानव विकास

विगत चौथाई सदी में विश्व बदल गया है – और इसके साथ ही विकास का भूदृश्य भी बदल गया है। नए देश उभर आए हैं और हमारा ग्रह अब 7 बिलियन से अधिक लोगों का घर है, जिनमें चार में से एक व्यक्ति युवा है।¹ भूराजनीतिक दृश्य भी बदल गया है और विकासशील देश बड़ी आर्थिक शक्ति और राजनीतिक सत्ता के रूप में उभर आए हैं। वैश्वीकरण ने लोगों, बाजारों और कार्य को एकीकृत किया है और डिजिटल क्रांति ने मानव जीवन को बदल दिया है।

विगत 25 वर्षों के दौरान मानव विकास की प्रगति प्रभावशाली रही है। लोग अब अधिक समय तक जीवित रहते हैं, अधिक बच्चे स्कूलों में हैं और मूलभूत सामाजिक सेवाएं अधिक लोगों तक पहुंच रही हैं।² सहस्राब्दि घोषणा और सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों – अर्थात् सदी के बदलने पर 15 वर्षों के भीतर मूलभूत मानव अभाव और वंचनाओं को समाप्त करने की वैश्विक प्रतिबद्धताओं – ने इसे और भी गति प्रदान की है।

फिर भी मानव विकास असमान रहा है और मानव अभाव तथा वंचनाएं अभी भी बनी हुई हैं। प्रगति समूहों, समुदायों और समाजों को अनदेखा करके गुजर गई है – और लोग पीछे छूट गए हैं। कुछ लोगों ने केवल मानव विकास के मूल तत्व अर्जित किए हैं और कुछ को तो वह भी हासिल नहीं हो सका है। विकास की नई चुनौतियां उभर आई हैं, जो असमानताओं से जलवायु परिवर्तन तक, महामारियों से अंधाधुंध प्रवासन तक, टकरावों से हिंसक उग्रवाद तक फैली हैं।

2016 की मानव विकास रिपोर्ट इस विषय पर केंद्रित है कि हर एक के लिए मानव विकास कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है – अभी और भविष्य में (सामने के पृष्ठ पर सूचना-रेखांकन 1 देखें)। इसमें आरंभ में मानव प्रगति के लिए उपलब्धियों, चुनौतियों और आशाओं का लेखाजोखा दिया गया है और भविष्य की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है कि मानवता कहाँ जाना चाहती है। इसकी दृष्टि सतत विकास के एजेंडा 2030 से ली गई है और उसे आगे बढ़ाती है, जिस पर पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे और उन 17 सतत विकास लक्ष्यों से भी, जिन्हें विश्व ने हासिल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।³

रिपोर्ट छानबीन करती है कि मानव विकास की प्रगति में कौन-कौन पीछे छूट गया है और क्यों। यह कहती है कि हर एक के लिए मानव विकास सुनिश्चित करने के लिए अभाव और वंचनाओं के स्वरूप और स्थान का ठीक-ठीक पता लगाना ही काफी नहीं है। मानव विकास दृष्टिकोण और आकलन परिप्रेक्ष्यों के कुछ पहलुओं को प्रमुखता देनी होगी। रिपोर्ट उन राष्ट्रीय नीतियों और प्रमुख रणनीतियों की भी पहचान करती है जो हर एक मनुष्य को मूलभूत मानव विकास

हासिल करने और इसके लाभों की साज-संभाल और सुरक्षा करने में सक्षम बनाएंगी। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की ढांचागत चुनौतियों को संबोधित करते हुए यह सांस्थानिक सुधारों के विकल्प प्रस्तुत करती है।

प्रमुख संदेश

यह रिपोर्ट पांच आधारभूत संदेश देती है :

- सार्वभौमिकतावाद मानव विकास की कुंजी है और हर एक के लिए मानव विकास प्राप्त किया जा सकता है।
- लोगों के विभिन्न समूह अब भी आधारभूत अभावों से ग्रस्त हैं और उनसे उबरने में उन्हें ठोस अवरोधों का सामना करना पड़ता है।
- हर एक के लिए मानव विकास कुछ विश्लेषणात्मक मुद्दों और आकलन परिप्रेक्ष्यों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की मांग करता है।
- नीतिगत विकल्प विद्यमान हैं और यदि उन्हें क्रियान्वित किया जाए तो वे हर एक के लिए मानव विकास हासिल करने में सहायक होंगे।
- अधिक बहुपक्षवाद के साथ सुधरी हुई निष्पक्ष वैश्विक शासन व्यवस्था हर एक के लिए मानव विकास हासिल करने में सहायता करेगी।

मानव विकास का निचोड़ है हर एक मानव के लिये स्वतंत्रताओं का विस्तार करना

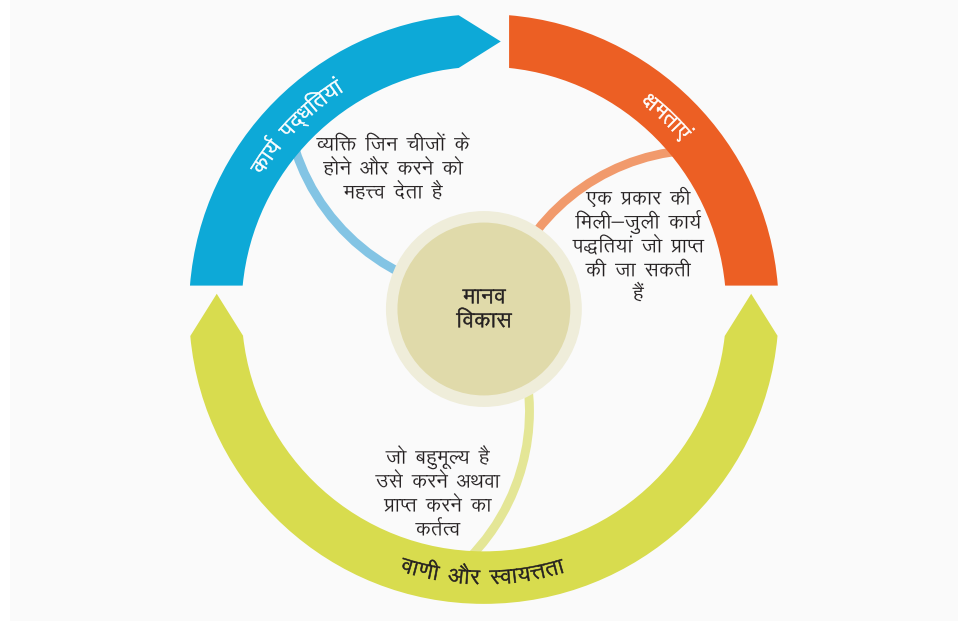
मानव विकास का निचोड़ स्वतंत्रताओं का विस्तार करना है ताकि सभी मनुष्य अपने लिए चयनित मूल्यों को पाने का प्रयत्न कर सकें। ऐसी स्वतंत्रताओं के दो आधारभूत पहलू हैं – सकुशल होने की स्वतंत्रता, जो क्रियाकलापों और क्षमताओं में परिलक्षित होती है, और कर्तव्य की स्वतंत्रता, जो वाणी और स्वायत्तता में दिखाई देती है (चित्रांकन 1)।

- क्रियाकलाप कई प्रकार के हैं जिनका होना और करना एक व्यक्ति के लिए मूल्यवान हो सकता है – जैसे प्रसन्न होना, पर्याप्त पोषण प्राप्त करना और

सार्वभौमिकतावाद मानव विकास की कुंजी है और हर एक के लिए मानव विकास प्राप्त किया जा सकता है।

चित्रांकन 1

मानव विकास – विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण



स्रोत : मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय

मानव विकास अर्थव्यवस्थाओं की संपन्नता मात्र की अपेक्षा मानव जीवन की संपन्नता पर ध्यान केंद्रित करता है

स्वस्थ होना तथा साथ ही आत्मसम्मान रखना और समुदाय के जीवन में भाग लेना।

- क्षमताएं क्रियाकलापों (होने और करने) के विभिन्न समूह हैं जो एक व्यक्ति अर्जित कर सकता है।
- कर्तव्य उस चीज से जुड़ा होता है जो एक व्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र है और वह जिन भी लक्ष्यों या मूल्यों को महत्त्वपूर्ण समझता है उन्हें पाने के प्रयत्न में अर्जित करता है।

दोनों प्रकार की स्वतंत्रताएं मानव विकास के लिए परम आवश्यक हैं।

1990 में पहली मानव विकास रिपोर्ट ने मानव विकास को विकास के जन-केंद्रित दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया था (बॉक्स 1)।⁴ इस बीच विकास के विमर्श में मानव विकास का दृष्टिकोण भौतिक समृद्धि का पीछा करने से बदलकर मानव सकुशलता को बढ़ाने पर, आय को अधिकाधिक बढ़ाने से बदलकर क्षमताओं को बढ़ाने पर, वृद्धि को ईष्टतम करने से बदलकर स्वतंत्रताओं को बढ़ाने आ गया। इसने अर्थव्यवस्थाओं की संपन्नता मात्र की अपेक्षा मानव जीवन की संपन्नता पर ध्यान केंद्रित किया, और ऐसा करते हुए विकास के परिणामों को देखने का नजरिया बदल दिया (बॉक्स 2)।

बॉक्स 1

मानव विकास – एक समग्र दृष्टिकोण

मानव विकास लोगों के विकल्पों को विस्तार देने की प्रक्रिया है। किंतु मानव विकास एक उद्देश्य भी है, इसलिए यह प्रक्रिया और परिणाम दोनों हैं। मानव विकास का निहितार्थ यह है कि लोगों को अपने जीवन को आकार देने वाली प्रक्रियाओं को प्रभावित करना ही चाहिए। इस सब में आर्थिक वृद्धि मानव विकास का एक महत्त्वपूर्ण साधन तो है किंतु यह अपने आप में साध्य नहीं है।

मानव विकास है लोगों का विकास – मानवीय क्षमताओं के निर्माण के माध्यम से, लोगों के द्वारा – उनके जीवन को गढ़ने वाली प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, और लोगों के लिए – उनके जीवन को बेहतर बनाने के माध्यम से। यह मानव संसाधन दृष्टिकोण, मूलभूत आवश्यकता दृष्टिकोण और मानव कल्याण दृष्टिकोण जैसे दूसरे दृष्टिकोणों से कहीं अधिक व्यापक है।

स्रोत : मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय

मानव विकास को मापना

समग्र मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) मानव विकास के तीन मूलभूत आयामों को समाहित करता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा या संभावित कुल आयु लंबी और स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता को प्रतिबिंबित करती है। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के संभावित वर्ष ज्ञान अर्जित करने की क्षमता दर्शाते हैं। और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से शालीन जीवन स्तर हासिल करने की क्षमता की झलक मिलती है।

अधिक विशद रूप से मानव विकास को मापने के लिए मानव विकास रिपोर्ट चार अन्य समग्र सूचकांक भी प्रस्तुत करती है। असमानता-समायोजित एच.डी.आई. असमानता की सीमा के अनुसार एच.डी.आई. में कटौती कर देता है। लैंगिक विकास सूचकांक महिला और पुरुष एच.डी.आई. मानों की तुलना करता है। लैंगिक असमानता सूचकांक महिला सशक्तीकरण पर प्रकाश डालता है। और बहुआयामी निर्धनता सूचकांक निर्धनता के आयवहीन आयामों को मापता है।

स्रोत : मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय

मानव विकास दृष्टिकोण ने सहस्राब्दि घोषणा और सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को सुदृढ़ विश्लेषणात्मक आधार भी प्रदान किया। ये विकास के समयबद्ध उद्देश्य और लक्ष्य थे, जिन पर वर्ष 2000 में 189 शासन प्रमुख और सरकारें वर्ष 2015 तक आधारभूत मानव निर्धनता को घटाने के लिए सहमत हुए थे। और इन्होंने एजेन्डा 2030 तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्रेरित और प्रभावित किया था।

हर एक के लिए मानव विकास प्राप्त किया जा सकता है

चूंकि मानव विकास सार्वभौमिकतावाद का केंद्रीय मुद्दा है, इसलिए हर एक के लिए मानव विकास प्राप्त किया ही जाना चाहिए और किया जा सकता है। इसके पक्ष में प्रमाण उत्साहवर्धक हैं।

विश्व ने 2015 तक उनमें से कुछ उपलब्धियां अर्जित कर ली थीं, जो 25 वर्ष पहले तक विकट चुनौतियां जान पड़ती थीं। यद्यपि विश्व की जनसंख्या में 2 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है और यह 1990 में 5.3 बिलियन से बढ़कर 2015 में 7.3 बिलियन पर पहुंच गई, किंतु 1 बिलियन से अधिक लोगों को चरम निर्धनता से छुटकारा मिला, 2.1 बिलियन लोगों को बेहतर स्वच्छता तक पहुंच हासिल हुई और 2.6 बिलियन से अधिक लोग पेयजल के बेहतर स्रोतों तक पहुंच सके।⁶

पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की वैश्विक मृत्यु दर 1990 से 2015 के बीच आधी से कम रह गई – प्रति 1,000 यह 91 जीवित बच्चों से घटकर 43 पर आ गई। एचआईवी, मलेरिया और तपेदिक या क्षयरोग के मामलों में 2000 से 2015 के बीच कमी आई। विश्व भर की संसदों में महिलाओं द्वारा आसीन सीटों की संख्या का अनुपात 2016 में बढ़कर 23 हो गया – जो इससे पहले के दशक से 6 प्रतिशतता अंक अधिक है। वनाच्छादित क्षेत्रों की वैश्विक निवल हानि 1990 के दशक में एक

वर्ष में 7.3 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 2010–2015 के दौरान 3.3 मिलियन पर आ गई।⁶

इस समूची सराहनीय प्रगति के बाद भी विश्व विकास की अनेक जटिल चुनौतियों से घिरा है। कुछ चुनौतियां लंबे समय से कायम हैं (अभाव और वंचनाएं), कुछ गहरी हो रही हैं (असमानताएं) और कुछ उभर रही हैं (हिंसक उग्रवाद)। कुछ चुनौतियां वैश्विक (लैंगिक असमानता), कुछ क्षेत्रीय (पानी का दबाव) और कुछ स्थानीय (प्राकृतिक आपदाएं) हैं। अधिकांश एक दूसरे को मजबूत करती हैं – जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा को कम करता है, द्रुत शहरीकरण शहरी गरीबों को कमजोर करता है। ये चुनौतियां लोगों की सकृशलता पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, फिर इनका फैलाव चाहे जितना हो।

इन समस्त चुनौतियों के होते हुए भी विगत 25 वर्षों में मानव जाति ने जो अर्जित किया है, वह आशा जगाता है कि आधारभूत बदलाव संभव है। वास्तव में, कुछ प्रभावशाली उपलब्धियां ऐसे क्षेत्रों या अंचलों में हासिल हुई हैं जो कभी पिछड़ रहे थे। विश्व भर में लोगों को उन प्रक्रियाओं को प्रभावित करने से अधिकाधिक जोड़ा जा रहा है जो उनके जीवन को गढ़ती हैं। मानवीय विदग्धता और सर्जनात्मकता ने प्रौद्योगिकीय क्रान्तियां आरंभ की हैं और उन्हें हमारे काम करने, सोचने और व्यवहार करने के तरीकों में परिवर्तित किया है।

लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तीकरण अब विकास के किसी भी विमर्श की मुख्यधारा बन गया है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कभी निषिद्ध माने जाने वाले मुद्दों पर चर्चा और संवादों की गुंजाइश, रचनात्मक रूप से उन पर विजय प्राप्त करने के इरादे के साथ, धीरे-धीरे खुल रही है – जैसा कि यौन उन्मुखता, महिला समलैंगिक, पुरुष समलैंगिक, उभयलैंगिक, लिंगपरिवर्तित तथा अंतरलिंगी लोगों के साथ हो रहे पक्षपातों, और महिला जननेंद्रि के उच्छेदन और काटछांट के मामलों में हुआ है।

सातत्य या स्थायित्व की जागरूकता बढ़ रही है। एजेन्डा 2030 और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता

विगत 25 वर्षों में मानव जाति ने जो अर्जित किया है, वह आशा जगाता है कि आधारभूत बदलाव संभव है। कुछ प्रभावशाली उपलब्धियां ऐसे क्षेत्रों या अंचलों में हासिल हुई हैं जो कभी पिछड़ रहे थे

मानव विकास के अंतरों को पाटना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु उतना ही महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना भी है कि भावी पीढ़ियों को समान, या बल्कि बेहतर, अवसर मिलें

इसके प्रमुख उदाहरण हैं। वे यह भी दर्शाते हैं कि बहस के कोलाहल और गतिरोध के नीचे अनेक वैश्विक चुनौतियों के उस पार एक नवोदित वैश्विक सर्वानुमति भी उभर रही है और भावी पीढ़ियों के लिए सतत विश्व सुनिश्चित कर रही है।

ये सभी आशाजनक घटनाक्रम विश्व को यह विश्वास दिलाते हैं कि चीजें बदली जा सकती हैं और आमूल परिवर्तन संभव हैं। विश्व के पास किसी को भी पीछे न छूटने देने के अपने प्रेरणास्पद एजेंडे को हासिल करने के लिए 15 वर्षों से भी कम समय है। मानव विकास के अंतरों को पाटना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु उतना ही महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना भी है कि भावी पीढ़ियों को समान, या बल्कि बेहतर, अवसर मिलें।

और एजेंडा 2030 को पूरा करना सभी लोगों को अपनी क्षमताओं के शिखर पर पहुंचने में सक्षम बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। वास्तव में मानव विकास दृष्टिकोण और एजेंडा 2030 में तीन साझा विश्लेषणात्मक कड़ियां हैं (चित्रांकन 2) :

- दोनों अपना आधार सार्वभौमिकतावाद से प्राप्त करते हैं – मानव विकास दृष्टिकोण हर एक मनुष्य के लिए स्वतंत्रताओं को बढ़ाने पर बल देकर और एजेंडा

2030 किसी को भी पीछे न छूटने देने पर ध्यान केंद्रित करके।

- दोनों साझा रूप से समान आधारभूत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं – चरम निर्धनता का उन्मूलन, भूख की समाप्ति, असमानता को कम करना, लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, इत्यादि।
- दोनों का मूल सिद्धांत सातत्यता है।

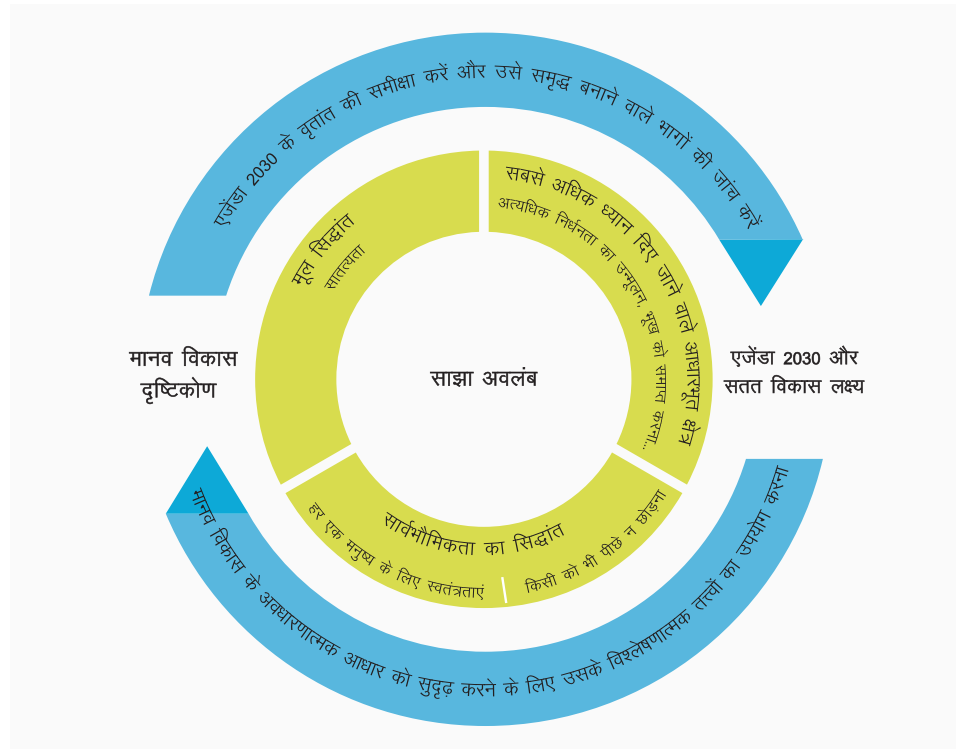
मानव विकास दृष्टिकोण, एजेंडा 2030 और सतत विकास लक्ष्यों के बीच की कड़ियां तीन तरीकों से एक दूसरे को मजबूती प्रदान करती हैं। पहला, एजेंडा 2030 देख सकता है कि मानव विकास दृष्टिकोण के कौन-कौन से विश्लेषणात्मक भाग उसके अवधारणात्मक आधार को सुदृढ़ करते हैं। इसी प्रकार मानव विकास दृष्टिकोण एजेंडा 2030 के वर्णन की समीक्षा कर सकता है और उन भागों की जांच-पड़ताल कर सकता है जो उसे समृद्ध बना सकते हैं।

दूसरा, सतत विकास लक्ष्य संकेतक सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का आकलन में मानव विकास संकेतकों का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार मानव विकास दृष्टिकोण सतत विकास लक्ष्य संकेतकों में अतिरिक्त संकेतक जोड़ सकता है।

तीसरा, मानव विकास रिपोर्ट एजेंडा 2030 और सतत विकास लक्ष्यों के समर्थन के लिए अत्यंत शक्तिशाली साधन

चित्रांकन 2

मानव विकास दृष्टिकोण और एजेंडा 2030 के बीच विश्लेषणात्मक कड़ियां



स्रोत : मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय

बन सकती है। और सतत विकास लक्ष्य अच्छा मंच बन सकते हैं जहां आने वाले वर्षों में मानव विकास दृष्टिकोण और मानव विकास रिपोर्ट अधिक स्पष्टता से दिखाई दे सकते हैं।

तो भी लोगों के विभिन्न समूहों के बीच मूलभूत अभाव और वंचनाएं बहुतायत से हैं

विश्व में नौ में से एक व्यक्ति भूखा है और तीन में से एक व्यक्ति कुपोषित है।⁷ लगभग 15 मिलियन लड़कियां प्रति वर्ष 18 वर्ष से कम आयु में ब्याही जाती हैं अर्थात् हर एक दूसरे सेकंड में एक।⁸ विश्व भर में 18,000 लोग प्रति दिन वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं,⁹ और एचआईवी प्रति वर्ष 2 मिलियन लोगों को संक्रमित करता है।¹⁰ प्रति मिनट औसतन 24 लोग अपने घरों से विस्थापित हो जाते हैं।¹¹

ऐसी आधारभूत अपवंचनाएं विभिन्न समूहों के बीच सामान्य हैं। महिलाएं और लड़कियां, जातीय अल्पसंख्यक, मूल देशज लोग, अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्ति, प्रवासी – ये सभी मानव विकास के मूलभूत आयामों की दृष्टि से वंचित हैं।

सभी क्षेत्रों में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा या संभावित आयु पुरुषों की अपेक्षा अधिक लंबी है और अधिकांश क्षेत्रों में लड़कियों की स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष लड़कों के समान ही हैं। तो भी सभी अंचलों में महिलाओं का औसतन मानव विकास सूचकांक मान पुरुषों की अपेक्षा लगातार निम्नतर बना हुआ है। सबसे अधिक अंतर दक्षिण एशिया में है जहां महिला एच.डी.आई. मान पुरुष एच.डी.ई. मान से 20 प्रतिशत कम है।

समूह आधारित अलाभप्रद स्थितियां हैं, जैसा कि नेपाल में दर्शाया गया है। ब्राह्मण और क्षत्रियों का मानव विकास सूचकांक मान सबसे अधिक (0.538) है, जिसके उपरांत जनजातियों (0.482), दलितों (0.434) और मुसलमानों (0.422) का स्थान है। सबसे विकट असमानताएं शिक्षा में हैं, जिनके क्षमताओं पर लंबे समय तक बने रहने वाले सुस्पष्ट प्रभाव पड़ते हैं।¹²

विभिन्न समूहों में मूलभूत मानव विकास की न्यूनताएं प्रायः भेदभाव के कारण बनी रहती हैं। महिलाओं के साथ अवसरों के संबंध में विशेष रूप से भेदभाव होता है और उन्हें अलाभप्रद परिणाम भुगतने पड़ते हैं (चित्रांकन 2)। कई समाजों में महिलाओं के साथ उत्पादक परिसंपत्तियों जैसे भूमि और संपत्ति के अधिकार के मामले में भेदभाव किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप विकासशील देशों में केवल 10–12 प्रतिशत भूस्वामी ही महिलाएं हैं।¹³

जातीय अल्पसंख्यकों और अन्य समूहों को प्रायः शिक्षा, रोजगार और प्रशासनिक तथा राजनीतिक पदों से बाहर रखा जाता है, जिसका परिणाम निर्धनता और मानव तस्करी सहित अपराधों के समक्ष उच्चतर वधयता या विवशता के रूप में सामने आता है। वियतनाम में

2012 में 51 प्रतिशत जातीय अल्पसंख्यक बहुआयामी निर्धनता में जीवनयापन कर रहे हैं, जबकि जातीय बहुसंख्या किन्ह या होआ लोगों के केवल 17 प्रतिशत लोग ही इस अवस्था में थे।¹⁴

70 देशों में 370 मिलियन से अधिक स्व-चिह्नित मूल देशज लोगों को भी वैधानिक ढांचे में, स्वयं अपनी भाषा में शिक्षा की सुगमता में और भूमि, जल, वन तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुलभता में भेदभाव और अपवर्जना का सामना करना पड़ता है।¹⁵

अनुमानित रूप से एक बिलियन से अधिक लोग किसी न किसी रूप में अक्षमता के साथ जीते हैं और अधिकांश समाजों में ये सबसे अधिक उपेक्षित लोगों में से हैं। वे लांछन, भेदभाव और असुगम्य शारीरिक और अप्रत्यक्ष वातावरणों से घिरे हैं।¹⁶

आज 244 मिलियन लोग अपने स्वदेश से बाहर रहते हैं।¹⁷ इनमें से कई आर्थिक शरणार्थी हैं जो अपनी आजीविकाओं को बढ़ाने और धन अपने घर भेजने की आशा से बाहर रहते हैं। किंतु अनेक प्रवासी, विशेषकर विश्व के 65 मिलियन बलपूर्वक विस्थापित लोग, दुर्बल स्थितियों का सामना करते हैं – वे आपात मानवीय सहायता से आगे नौकरियों, आय और स्वास्थ्य देखभाल तथा सामाजिक सेवाओं से वंचित हैं। उन्हें मेजबान देशों में प्रायः उत्पीड़न, वैमनस्य और हिंसा का सामना करना पड़ता है।

मानव अभावों की अपनी गत्यात्मकता भी है। मानव विकास की निचली सीमाओं से ऊपर आना आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित नहीं करता कि लोग उभरते और भावी खतरों से बचे रहेंगे। यहां तक कि जहां लोगों के पास पहले की तुलना में अधिक विकल्प हैं भी, वहां इन विकल्पों की सुरक्षा को खतरा हो सकते हैं।

महामारियां, हिंसा, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं निर्धनता से बाहर निकल आए लोगों की प्रगति को तेजी से खोखला कर सकती हैं। वे नए अभाव भी उत्पन्न कर सकते हैं। विश्व भर में लाखों लोग अवक्रमित भूमि पर गुजारा करते हुए जलवायु से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं, सूखे और उनसे जुड़ी खाद्य असुरक्षाओं के आगे अनावृत हैं।

वर्तमान पीढ़ी के अभाव और वंचनाएं अगली पीढ़ी को मिल सकती हैं। माता-पिता की शिक्षा, स्वास्थ्य और आय उनके बच्चों को उपलब्ध अवसरों को बहुत अधिक सीमा तक प्रभावित कर सकती हैं।

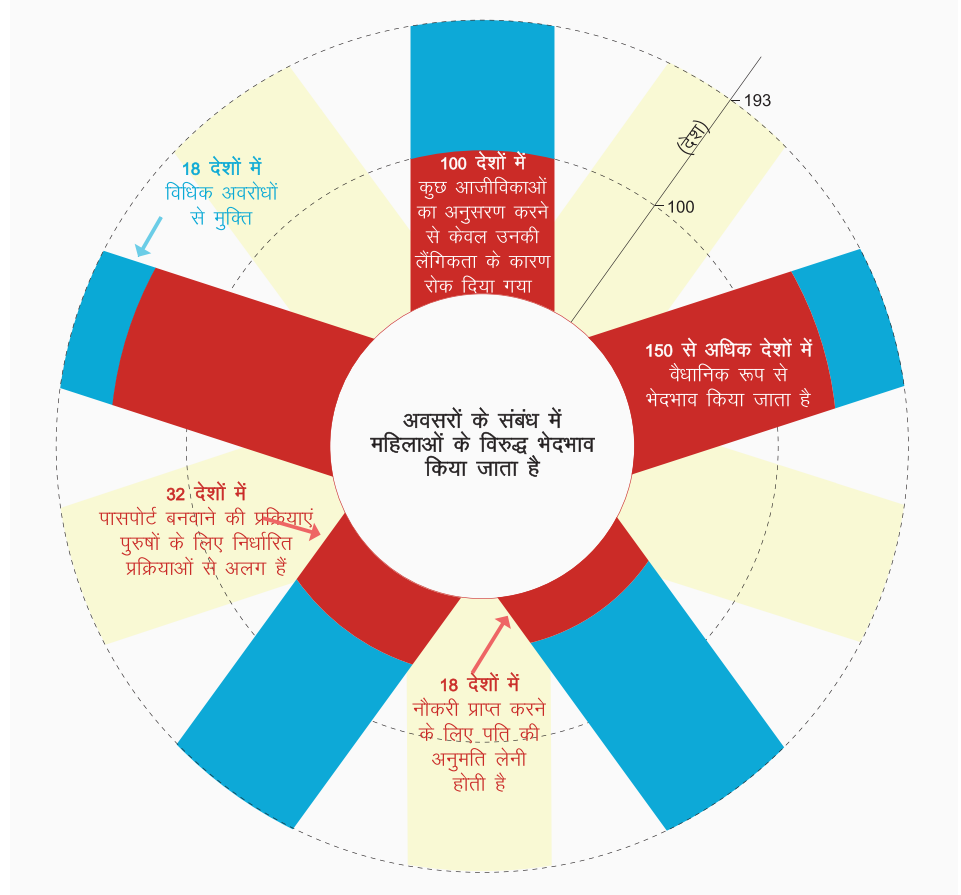
सार्वभौम मानव विकास के लिए ठोस अवरोध कायम हैं

लोगों के उन समूहों तक पहुंचना सबसे अधिक कठिन हो सकता है, जो वंचित बने रहते हैं, – भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से। इन अवरोधों को पार करने के लिए कहीं अधिक मात्रा में राजकोषीय संसाधनों और विकास सहायता की, प्रौद्योगिकी के निरंतर लाभों की और निगरानी तथा

मानव अभावों की अपनी गत्यात्मकता है। मानव विकास की निचली सीमाओं से ऊपर आना आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित नहीं करता कि लोग उभरते और भावी खतरों से बचे रहेंगे

चित्रांकन 3

अवसरों के संबंध में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव किया जाता है



स्रोत : मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय

सार्वभौम मानव विकास को व्यवहार में साकार करना संभव है, किंतु पहले प्रमुख अवरोधों और विभिन्न प्रकार के अपवर्जनों पर विजय पाना अत्यंत आवश्यक है

मूल्यांकन के लिए बेहतर आंकड़ों और जानकारी की आवश्यकता हो सकती है।

किंतु कुछ अवरोध सामाजिक तथा राजनीतिक पहचानों और संबंधों – जैसे प्रबल हिंसा, भेदभावपूर्ण विधि-विधान, बहिष्कारक सामाजिक मान्यताएं, राजनीतिक भागीदारी में असंतुलन और अवसरों के असमान वितरण – में गहराई से धंसे हुए हैं। इन पर विजय पाने के लिए समानुभूति, सहिष्णुता और वैश्विक न्याय तथा सातत्यता के प्रति नैतिक वचनबद्धताओं को वैयक्तिक और सामूहिक चयनों के केंद्र में रखने की आवश्यकता होगी। लोगों को स्वयं को प्रतिद्वंद्वी समूहों और हितों के विखंडित भूभाग की अपेक्षा सामंजस्यपूर्ण वैश्विक समष्टि का भाग समझना चाहिए।

सार्वभौम मानव विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इस बात के प्रति जागरूक होना और इसे समझना आवश्यक है कि लोगों को हाशियों पर धकेल दिए जाने के पीछे कौन से चालक और गत्यात्मकताएं हैं, जो

अनिवार्यतः देशों और क्षेत्रों के अनुसार अलग-अलग हैं। सार्वभौम मानव विकास को व्यवहार में साकार करना संभव है, किंतु पहले प्रमुख अवरोधों और विभिन्न प्रकार के अपवर्जनों पर विजय पाना अत्यंत आवश्यक है (चित्रांकन 4)।

अपवर्जन या बहिष्कार जानबूझकर हों या अनजाने में, उनके परिणाम समान ही हो सकते हैं – कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक वंचित होंगे और सभी लोगों को अपनी पूर्ण क्षमताओं को साकार करने के लिए समान अवसर नहीं मिलेंगे। समूह की असमानताओं में सामाजिक रूप से निर्मित और कायम विभाजनों की झलक मिलती है क्योंकि वे मूल्यवान परिणामों और अत्यल्प संसाधनों तक असमान पहुंच के लिए आधार स्थापित करते हैं। अपवर्जन के आयाम और तंत्र भी गतिशील हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे समूह बहिष्कार या अपवर्जन के लिए जिन आधारों का उपयोग करते हैं उनकी चारित्रिकताएं गतिशील हैं।

चित्रांकन 4

सार्वभौमिकतावाद के अवरोध



स्रोत : मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय

समूह विभाजनों को बनाए रखने के लिए विधिक और राजनीतिक संस्थाओं का उपयोग और दुरुपयोग किया जा सकता है। एक चरम मामला 73 देशों और पांच भूभागों में महिला समलैंगिकों, पुरुष समलैंगिकों, लिंगपरिवर्तितों और अंतरयौन समुदायों के अधिकारों से जुड़ा है, जहां समान-लैंगिक यौन क्रीड़ाएं अवैधानिक हैं।¹⁸ दूसरे मामलों में भी विधि-विधान भेदभावपूर्ण हैं क्योंकि वे कुछ निश्चित समूहों को सेवाओं या अवसरों तक पहुंचने से रोकते हैं।

समाजों के भीतर सौहार्दपूर्ण सहअस्तित्व के लिए कुछ सामाजिक मान्यताएं सहायक हो सकती हैं, किंतु कुछ अन्य सामाजिक मान्यताएं भेदभावी, पूर्वाग्रही और अपवर्जक हो सकती हैं। कुछ देशों में सामाजिक मान्यताएं महिलाओं और लड़कियों के विकल्पों और अवसरों को कम कर देती हैं, जो तीन-चौथाई से अधिक पारिवारिक कार्य बिना किसी भुगतान के करने के लिए विशिष्ट रूप से उत्तरदायी हैं।¹⁹ कैफे और रेस्तरांओं में ग्राहक के रूप में महिलाओं की उपस्थिति को हतोत्साहित किया जा सकता है और कुछ मामलों में महिलाओं के लिए पुरुष को साथ लिए बिना खुलेआम यात्रा करना निषिद्ध है।²⁰

अपवर्जन या बहिष्कार का सबसे सीधा तरीका संभवतः हिंसा है। उत्प्रेरकों में राजनीतिक सत्ता को मजबूत करना, अभिजनों की सकुशलता की रक्षा करना, संसाधनों के वितरण पर नियंत्रण करना, भूभागों और संसाधनों पर कब्जा करना और एक पहचान या मूल्यों के समूह की श्रेष्ठता पर आधारित विचारधाराओं पर पक्षपातपूर्ण कृपा करना शामिल हैं।

वैश्विक संपदा वितरण के शीर्ष 1 प्रतिशत के पास विश्व की 46 प्रतिशत संपदा है।²¹ आय में असमानताएं सकुशलता के अन्य आयामों में असमानताओं को प्रभावित करती हैं और इसका ठीक उल्टा भी होता है। वर्तमान असमानताओं को देखते हुए बहिष्कृत समूह इतनी कमजोर स्थिति में हैं कि संस्थाओं के कार्यालय की पहल नहीं कर सकते। उनमें कर्तव्य और वाणी की कमी है और इसलिए इतना राजनीतिक बल नहीं है कि पारंपरिक साधनों से नीतियों और विधि निर्माण को प्रभावित कर सकें।

ऐसे समय में जब वैश्विक कार्यवाही और सहकार्य अत्यंत आवश्यक है, आत्म-पहचानें संकीर्ण होती जा रही हैं। पहचान से जुड़े सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन, चाहे वे राष्ट्रवादी हों या जातीय-राजनीतिक हों, और सुदृढ़ होते जान पड़ते हैं। ब्रेक्जिट सबसे हाल

आय में असमानताएं सकुशलता के अन्य आयामों में असमानताओं को प्रभावित करती हैं और इसका ठीक उल्टा भी होता है

ही के उदाहरणों में से एक है जो बताता है कि जब बदलते हुए विश्व में व्यक्तियों को अलगाव की अनुभूति होती है तो वे पीछे लौटकर कैसे राष्ट्रवाद की शरण में जाते हैं।

दूसरों की असहिष्णुता के सभी रूप – विधिक, सामाजिक और अवपीड़क – मानव विकास और सार्वभौमिकतावाद के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत हैं।

हर एक के लिए मानव विकास कुछ विश्लेषणात्मक मुद्दों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की मांग करता है

मानव विकास में विकल्पों को बढ़ाना शामिल है। ये विकल्प ही निर्धारित करते हैं कि हम कौन हैं और क्या करते हैं। कई कारक इन चुनावों की बुनियाद में होते हैं : विभिन्न प्रकार के विकल्प जिनमें से हमें चुनना होता है – हमारी क्षमताएं, सामाजिक और संज्ञानात्मक बाध्यताएं और सामाजिक मान्यताएं तथा प्रभाव जो हमारे मूल्यों और चयनों को गढ़ते हैं, स्वयं हमारा सशक्तीकरण और कर्तव्य जिसका प्रयोग हम अपने विकल्पों और अवसरों को गढ़ने में वैयक्तिक रूप से और समूह के अंग के रूप में करते हैं, और वे तंत्र जो प्रतिस्पर्धी दावों को निष्पक्ष तथा मानव क्षमता को साकार करने के अनुकूल तरीकों से सुलझाने के लिए मौजूद हैं।

मानव विकास दृष्टिकोण इन विचारों को स्पष्ट ढंग से व्यक्त करने के लिए व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है। यह उन कारकों की परस्पर भूमिका पर प्रकाश डालने में विशेष रूप से शक्तिशाली है जो अलग-अलग संदर्भों में व्यक्तियों और समूहों को अलाभप्रद स्थितियों में रखने के लिए कार्य कर सकते हैं।

मानव अधिकार मानव विकास का अत्यंत शक्तिशाली आधार हैं। मानव विकास का विश्लेषण करने के लिए मानव अधिकार उपयोगी परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। कर्तव्यधारक मानव विकास का समर्थन और संवर्धन करते हैं और ये मानव विकास कर पाने में सामाजिक प्रणाली की विफलता के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये परिप्रेक्ष्य न केवल मानव विकास के अल्पतम दावों से आगे जाते हैं, बल्कि सुधार के उपायों की खोज में शक्तिशाली साधन का काम भी करते हैं।

मानव सुरक्षा की धारणा को मानव विकास और मानव सुरक्षा दृष्टिकोणों की संयुक्त कार्यवाही के लिए खतरों, जोखिमों और संकटों की गहरी समझ पर बल देना चाहिए। चुनौती यह है कि वैश्विक खतरों के आघात-संचालित प्रत्युत्तर देने और रोकथाम की संस्कृति को प्रोत्साहन देने में संतुलन लाया जाए।

वाणी और स्वायत्तता कर्तव्य की स्वतंत्रता और सकुशलता की स्वतंत्रता के अंग के रूप में मानव विकास से अभिन्न रूप से जुड़ी हैं। हर एक के लिए मानव विकास में विचार-विमर्श करने की, सार्वजनिक बहसों में भाग लेने की और अपने जीवन तथा वातावरण

को गढ़ने में अभिकर्ता होने की क्षमता का आधारभूत महत्त्व है। मानव विकास दृष्टिकोण का प्राथमिक ध्यान मोटे तौर पर सकुशलता की स्वतंत्रता पर रहा है। किंतु जब सकुशलता प्राप्त कर ली गई, तब कर्तव्य की स्वतंत्रता पर बल देना अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है।

मानव विकास केवल व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं को ही नहीं, बल्कि समूहों और संगठनों की स्वतंत्रताओं को भी बढ़ावा देता है। सबसे अधिक अधिकारहीन और सबसे अधिक वंचित लोगों के लिए सामूहिक संस्था व्यक्तिगत संस्था से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकती है। एक व्यक्ति के लिए अकेले अपने दम पर बहुत कुछ हासिल कर पाना असंभव है और सामूहिक कार्यवाही के माध्यम से ही शक्ति प्राप्त की जा सकती है।

पहचान कर्तव्य और स्वायत्तता को प्रभावित करती है। लोगों को अपनी पहचान चुनने की स्वतंत्रता हासिल है, जो पहचानने, महत्त्व देने और बचाव करने के लिए महत्त्वपूर्ण स्वतंत्रता है। व्यक्तियों को अपने लिए मूल्यवान नानाविध पहचानों में से चुनने के विकल्पों का अधिकार है। ऐसे विकल्पों को पहचानना और उनका सम्मान करना बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक समाजों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की पूर्व शर्त है।

सार्वभौम मानव विकास के लिए पहचान के तीन मुद्दों का अपना निहितार्थ है। पहला, अधिकारविहीन लोगों के बीच बहुत-सी पहचानों की गुंजाइश अधिक सीमित है और इन लोगों के पास अपने लिए मूल्यवान पहचान को चुनने की स्वतंत्रता का अभाव भी हो सकता है। दूसरा, एक ही अकाट्य पहचान का आग्रह और पहचानों के चयन में तर्क-वितर्क और पसंद से इनकार उग्रवाद और हिंसा की ओर ले जा सकता है और इस प्रकार मानव विकास के लिए खतरा उत्पन्न करता है। तीसरा, पहचान-समूह आर्थिक तथा राजनीतिक संसाधनों और शक्ति के लिए होड़ करते हैं और वंचित तथा अधिकारविहीन लोग इस होड़ में हार जाते हैं। अधिकांश मामलों में समाज के मूल्य और मान्यताएं सर्वाधिक सुविधाहीन लोगों के विरुद्ध जाती हैं, जहां वरीयताएं प्रायः विशेषाधिकार और अधीनता की सामाजिक परंपराओं से निर्धारित होती हैं। किंतु मूल्यों और मान्यताओं को बदलकर सुविधाहीन लोगों के विरुद्ध इन पूर्वाग्रहों को पूर्णतः बदला जा सकता है।

स्वतंत्रताएं अंतर्निर्भर हैं और ऐसी स्वतंत्रताएं परस्पर शक्तिवर्धक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक श्रमिक कार्यस्थल को हरित बनाने की स्वतंत्रता का प्रयोग करता है, तब वह दूसरे श्रमिकों की स्वच्छ हवा में सांस लेने की स्वतंत्रता में योगदान दे रहा हो सकता है। किंतु एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण भी कर रही हो सकती है। एक धनवान व्यक्ति को बहुमंजिला मकान बनवाने की स्वतंत्रता है, किंतु वह अपने एक निर्धन पड़ोसी को धूप और हवादार वातावरण से वंचित कर रहा हो सकता है।

एक व्यक्ति द्वारा स्वतंत्रता के प्रयोग का इच्छित परिणाम दूसरों की स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं भी हो सकता है, किंतु दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित

करने वाले कुछ कार्य जाने-बूझे भी हो सकते हैं। संपन्न और शक्तिशाली समूह दूसरों की स्वतंत्रता को कम करने का प्रयत्न कर सकते हैं। यह कई अर्थव्यवस्थाओं में, विधिक प्रणाली का जिस प्रकार निर्माण होता है तथा संस्थाएं जिस प्रकार कार्य करती हैं, उनमें संपन्नता के पक्ष में नीतिगत विकल्पों के पूर्वाग्रह में प्रतिबिंबित होता है। सभी समाजों को कुछ लेनदेन का रास्ता अपनाना पड़ता है और विवेकपूर्ण तर्क-वितर्क के पश्चात समय-समय पर उठने वाले मुद्दों को तेज गति से सुलझाने के लिए सिद्धांत निर्धारित करने पड़ते हैं और न्यायसंगत समाज साकार करना होता है।

सतत विकास सामाजिक न्याय का मुद्दा है। यह अंतरपीढ़ीगत समानता से जुड़ा है – अर्थात् भावी पीढ़ियों की और वर्तमान पीढ़ी की स्वतंत्रताएं। इस प्रकार मानव विकास दृष्टिकोण सातत्यता को एक पीढ़ी के भीतर और एक से दूसरी पीढ़ियों में वितरण की समानता का विषय मानता है।

विशिष्ट आकलन परिप्रेक्ष्य हर एक तक पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं

विकास कार्यकर्ता सिद्धांततः सहमत हैं कि सभी लोगों को मानव विकास की प्रगति का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए क्षेत्र, लैंगिकता, ग्रामीण-शहरी अवस्थिति, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, नस्ल और जातीयता के संबंध में अलग-अलग आंकड़ों और जानकारीयों की आवश्यकता होती है। किंतु ऐसे आंकड़ों और जानकारीयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में उन्हें ठीक-ठीक पता नहीं है। विशिष्ट आयामों से जुड़ी असमानताओं को उद्घाटित करने के लिए कौन-कौन-से अलग आंकड़ों की आवश्यकता है, यह निर्धारित करना पहले समाज की बहिष्कार और उपेक्षित करने की प्रक्रियाओं की कुछ समझ हासिल किए बिना कठिन हो सकता है। और राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संवेदनशीलताएं बहिष्कारों और वंचनाओं को बढ़ावा दे सकती हैं।

लैंगिकता के अनुसार आंकड़ों को अलग-अलग करना लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। ठीक यही कारण है कि एजेंडा 2030, विशेष रूप से लैंगिक समानता प्राप्त करने और सभी महिलाओं तथा लड़कियों को सशक्त बनाने से संबंधित सतत विकास लक्ष्य 5, पृथक लैंगिक आंकड़ों की सुलभता को आसान बनाने के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है।

यद्यपि कर्तव्य की स्वतंत्रता मानव विकास का अभिन्न अंग है, ऐसा होते हुए भी मानव विकास दृष्टिकोण ने पारंपरिक रूप से कर्तव्य की अपेक्षा सकुशलता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। जरा मानव विकास सूचकांक को देखिए। परंतु कर्तव्य को मापना

सकुशलता को मापने की अपेक्षा स्वाभाविक रूप से कहीं अधिक कठिन है।

सकुशलता की स्वतंत्रता और कर्तव्य की स्वतंत्रता के मध्य संबंध सामान्यतः सकारात्मक है। यह इस धारणा को बल देता है कि मानव विकास के ये दो पहलू यदि पूर्णतः सह-संबद्ध न भी हों तो अनुपूरक तो हैं ही। दूसरे शब्दों में, समाजों ने कर्तव्य (वाणी और स्वायत्तता में) प्राप्त किए बिना उच्च औसत क्षमताएं या सकुशलता प्राप्त करी हो सकती हैं।

मानव कुशलता के अन्य उपाय, जैसे सामाजिक प्रगति सूचकांक²², विश्व प्रसन्नता सूचकांक²³ और बेहतर जीवन सूचकांक²⁴, उपयोगी ढंग से आकलन कर सकते हैं कि सकुशलता हर एक तक पहुंच रही है या नहीं। कुछ देश सकुशलता या प्रसन्नता के व्यक्तिपरक उपायों का समर्थन करते हैं, जैसा कि भूटान में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक²⁵ करता है।

हर एक के लिए मानव विकास में नवाचारी परिप्रेक्ष्यों से आंकड़ों और जानकारी का संग्रह और प्रस्तुति भी निहित है, जैसे वास्तविक समय पर आंकड़े और नियंत्रणपट्ट। नियंत्रणपट्ट या डैशबोर्ड का तरीका रंग-कूटबद्ध सारणियों में विभिन्न विकास संकेतकों के अनुसार स्तरों और प्रगति को दर्शा सकता है। इस प्रकार यह मानव सकुशलता का आकलन करने में प्रभावी हो सकता है। इसमें एक समावेशी प्रक्रिया भी निहित है जो नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके अधिक लोगों को समाहित और सूचनाओं को प्रसारित करती है।

2013 में सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की उच्चस्तरीय समिति ने सतत विकास के लिए एक डाटा क्रांति का आह्वान किया था और उसके साथ ही नागरिकों को उपलब्ध सूचना और सांख्यिकियों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक नई अंतरराष्ट्रीय पहल आरंभ की थी।²⁶ बिग डाटा या बड़े डाटा का अर्थ है आंकड़ों की विशाल मात्रा – संरचित और असंरचित दोनों – जो विभिन्न संगठन नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके एकत्र करते हैं और जो पारंपरिक आंकड़ों तथा सांख्यिकियों को नया परिप्रेक्ष्य दे सकते हैं।

प्रमुख नीतिगत विकल्प

चार सूत्रीय राष्ट्रीय नीति अपनाकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि मानव विकास हर एक तक पहुंचे (चित्रांकन 5)। पहला, पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचने के लिए सार्वभौम नीतियों की आवश्यकता है, किंतु नीति में व्यावहारिक सार्वभौमिकतावाद चुनौतीपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एक देश सार्वभौम स्वास्थ्य सेवा के प्रति प्रतिबद्ध हो सकता है, किंतु जटिल भौगोलिक स्थिति उसे सभी स्थानों से पहुंच योग्य स्वास्थ्य सेवा केंद्र स्थापित करने से रोक सकती है। इसलिए सार्वभौम मानव विकास नीतियों की दिशा इस प्रकार निर्धारित करने की आवश्यकता है जिससे पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचा जा सके।

सतत विकास सामाजिक न्याय का एक मुद्दा है

छूट गए लोगों की देखभाल के लिए राष्ट्रीय नीतियां – चार-सूत्रीय रणनीति



दूसरे, यहां तक कि सार्वभौम नीतियों पर नए सिरे से ध्यान दिए जाने के साथ भी लोगों के कुछ समूहों की विशेष आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकेगा। उनकी स्थिति विशिष्ट उपायों और देखरेख की मांग करती है। उदाहरण के लिए, अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए ऐसे उपाय करने की आवश्यकता है जिनसे उनके लिए गतिशीलता, भागीदारी और कार्य अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।

तीसरे, मानव विकास अर्जित करने का अर्थ मानव विकास को सतत बनाए रखना नहीं है। झटकों और कमजोरियों के कारण मानव विकास की प्रगति धीमी हो सकती है या उलट भी सकती है, जिसके प्रभाव उन लोगों पर पड़ सकते हैं जिन्होंने केवल आधारभूत मानव

विकास अर्जित किया है या जिन्हें अभी आधारभूत मानव विकास भी अर्जित करना है। इसलिए मानव विकास को लोचदार होना होगा।

चौथा, पीछे छूट गए लोगों को सशक्त बनाना होगा, ताकि यदि नीतियां और संबंधित कर्ता परिणाम देने में विफल रहते हैं, तो ये लोग स्वयं अपनी आवाज उठा सकें, अपने अधिकारों की मांग कर सकें और स्थिति में सुधार की चेष्टा कर सकें।

वैश्वीकृत विश्व में सार्वभौम मानव विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियों की कमियों को पूरा करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था होनी ही चाहिए जो निष्पक्ष हो और मानव विकास को समृद्ध करे।

सार्वभौम नीतियों के माध्यम से छूट गए लोगों तक पहुंचना

सार्वभौम नीतियों को सही दिशा देकर छूट गए लोगों के बीच मानव विकास की कमियों और न्यूनताओं को कम किया जा सकता है। इसके लिए अनिवार्य है कि समावेशी वृद्धि का अनुसरण किया जाए, महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ाया जाए, जीवनचक्र क्षमताओं को संबोधित किया जाए और मानव विकास की प्राथमिकताओं के लिए संसाधन जुटाए जाएं।

समावेशी वृद्धि का अनुसरण

मानव विकास को हर एक तक पहुंचाने के लिए वृद्धि को समावेशी होना होगा। इसके परस्पर सहायक चार स्तंभ हैं – वृद्धि की रोजगार-नीत कार्यनीति प्रतिपादित करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, मानव विकास प्राथमिकताओं में निवेश करना और उच्च प्रभाव वाले बहुआयामी हस्तक्षेपों (सभी के लिए लाभदायक रणनीतियों) का प्रयत्न करना।

वृद्धि की रोजगार-नीत कार्यनीति रोजगार केंद्रित विकास की बाधाओं को हटाने, अनौपचारिक कार्यों से निपटने के लिए अनुकूल नियमों के ढांचे का निर्माण और क्रियान्वयन करने, बड़े तथा छोटे तथा मध्यम आकार के उद्यमों के बीच कड़ियों को मजबूत करने, निर्धन लोगों के रहने और काम करने के क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, पर ध्यान देने और नौकरियों के सृजन के लिए सार्वजनिक परिव्यय में पूंजी और श्रम के वितरण को समायोजित करने जैसे उपायों पर ध्यान देगी।

अनेक उपाय निर्धन लोगों के वित्तीय समावेशन को बढ़ा सकते हैं, जैसे बैंकिंग सेवाओं का साधनहीन और उपेक्षित समूहों तक विस्तार करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरल प्रक्रियाओं पर विश्वास करना और आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना। अफ्रीका के उप-सहारा भूभाग में 12 प्रतिशत वयस्कों के पास मोबाइल फोन हैं, जबकि वैश्विक आंकड़ा 2 प्रतिशत है।²⁷

मानव विकास की प्राथमिकताओं पर केंद्रित निवेश वंचित और उपेक्षित समूहों को कम लागत की किंतु उच्च गुणवत्ता की सेवाएं और अवसंरचना प्रदान कर सकते हैं।

सेवाओं तक निर्धन लोगों की प्रभावी पहुंच के लिए लागत को वहनीय और सांस्कृतिक प्रथाओं को अनुकूलनीय बनाना आवश्यक है। निकारागुआ में कम लागत की अल्ट्रासोनोग्राम मशीनें, जिन्हें बाइसिकल पर ले जाया जा सकता है, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही हैं।²⁸ ग्रामीण जननी और बाल सेवा केंद्रों में केवल पुरुष डॉक्टरों की उपस्थिति महिलाओं और लड़कियों को इन केंद्रों का उपयोग करने से हतोत्साहित करने वाली होगी।

मानव विकास की प्राथमिकता वाले कुछ निवेशों के सुदृढ़ और बहुत-से प्रभाव हुए हैं। स्कूल भोजन कार्यक्रमों को ही लें, जिसके अनेक लाभ हैं: परिवारों की सहायता के माध्यम से प्रदान की गई सामाजिक सुरक्षा उनके बच्चों को शिक्षित करती है और संकट के समय उनके बच्चों की खाद्य सुरक्षा की रक्षा करती है, पोषण, क्योंकि निर्धन देशों में स्कूल भोजन प्रायः एकमात्र नियमित और पोषक आहार है, और बच्चों को स्कूल भेजने और स्कूलों में रखने के लिए सुदृढ़ प्रोत्साहन। बोत्सवाना, काबो, वर्ड, कोट डि आइवरी, घाना, केन्या, माली, नामीबिया, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रमाण इन लाभों के साक्षी हैं।²⁹

ग्रामीण आधारभूत ढांचा, विशेषकर सड़कें और बिजली, एक और क्षेत्र है। ग्रामीण सड़कों का निर्माण परिवहन लागत को कम करता है, ग्रामीण किसानों को बाजारों से जोड़ता है, श्रमिकों को अधिक स्वतंत्रता से आने-जाने की सुविधा प्रदान करता है और स्कूलों तथा स्वास्थ्य सेवा केंद्रों तक पहुंच को बढ़ाता है। ग्वाटेमाला और दक्षिण अफ्रीका के ग्रामीण समुदायों में बिजली पहुंचने से उपेक्षित समूहों के बीच रोजगार में बढ़ोतरी में सहायता मिली है।³⁰

मानव विकास को हर एक तक पहुंचाने के लिए वृद्धि को समावेशी होना होगा

परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण करके भी छूट गए लोगों को वृद्धि की प्रक्रिया में लाया जा सकता है। मानव पूंजी एक परिसंपत्ति है और शिक्षा प्राप्ति में अंतर तथा भिन्नताएं निर्धन लोगों को उच्च-उत्पादकता वाली वृद्धि प्रक्रिया का अंग बनने से रोकती हैं। शिक्षा के, विशेषकर तृतीयक शिक्षा के, लोकतांत्रिकीकरण से निर्धनतर पृष्ठभूमि के लोगों को लाभ मिलेगा।

इसी प्रकार चीजों को स्थानीय रूप से करने के विकास पर बहुत-से प्रभाव पड़ सकते हैं। स्थानीय सरकारों को स्थानीय विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में स्वायत्तता प्रदान करने से इन योजनाओं में स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं की झलक देखी जा सकती है। राजकोषीय विकेंद्रीकरण भी स्थानीय सरकारों को सशक्त बना सकता है, ताकि वे स्वयं अपना राजस्व एकत्र करें और केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता पर कम निर्भर रहें। किंतु स्थानीय दृष्टिकोण जहां छूट गए लोगों को मानव विकास सुनिश्चित करने के लिए है, वहीं इसके लिए लोगों की भागीदारी और कहीं अधिक स्थानीय प्रशासनिक क्षमता की भी आवश्यकता होगी।

महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ाना

लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तीकरण मानव विकास के आधारभूत आयाम हैं। चूंकि आधी मानव जाति मानव विकास की प्रगति का लाभ नहीं ले पा रही है, इसलिए ऐसा विकास सार्वभौम नहीं है।

लड़कियों और महिलाओं में निवेश करने के बहुआयामी लाभ हैं – उदाहरण के लिए, यदि विकासशील देशों में सभी लड़कियों ने सेकंडरी शिक्षा पूरी कर ली होती, तो पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर घटकर आधी हो जाती।³¹ महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी सहारे की जरूरत है, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित की उच्च शिक्षा के लिए, जिनमें भविष्य में उच्च स्तर के कार्यों की काफी मांग होगी।

महिलाओं को घर के बाहर वैतनिक रोजगार और घर के भीतर देखभाल के अवैतनिक कार्य को एक साथ संभालना पड़ता है और साथ ही अपनी उत्पादक तथा जननी भूमिकाओं में संतुलन भी साधना पड़ता है। लचीली कार्य व्यवस्थाएं और विस्तारित देखभाल विकल्प, जिनमें दिन की देखभाल के केंद्र, स्कूल-पश्चात कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिक गृह और दीर्घकालिक देखभाल सुविधा केंद्र भी शामिल हैं, अपने विकल्पों को बढ़ाने में महिलाओं की मदद कर सकते हैं।

महिलाओं की उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के उपायों में एक ऐसे विधिक ढांचे की स्थापना करना भी शामिल है जिससे महिलाओं के द्वारा विशेषकर कृषि क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिसंपत्ति भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने की बाधाओं को हटाया जा सके। इसलिए भू नीतियों, विधि-विधानों और प्रशासन में ऐसे बदलाव लाने की आवश्यकता है जिनसे महिलाओं को

स्थान दिया जा सके – और नए नियमों को अनिवार्यतः लागू भी करना होगा।

रुकावटों की अदृश्य दीवार कई स्थानों पर चटकी अवश्य है किंतु अभी थोड़ी भी टूटी नहीं है। चयन और भर्ती में लिंग संबंधी आवश्यकताएं और रोककर रखने के लिए प्रोत्साहन के व्यवस्थागत उपाय सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा सकते हैं। प्रबंधन के वरिष्ठ पदों पर पुरुषों और महिलाओं की पदोन्नति का मानदंड एक समान होना चाहिए और यह समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। मार्गदर्शन करके, प्रशिक्षण देकर और प्रायोजित करके महिलाओं को कार्य स्थल पर सशक्त बनाया जा सकता है और इसके लिये वरिष्ठ महिला प्रबंधकों का रोल मॉडल और प्रायोजक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

जीवनचक्र क्षमताओं को संबोधित करना

मानव विकास छूट गए लोगों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए क्षमताओं के निर्माण को जीवनचक्र की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को अपने जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न-भिन्न प्रकार की वधयताओं या कमजोरियों का सामना करना होता है।

सतत मानव विकास की संभावना तब और अधिक होती है जब सभी बच्चे कार्यबल से जुड़ने वाले युवाओं को प्राप्त अवसरों के अनुरूप कौशल हासिल कर सकें। इस बात पर उचित ही काफी ध्यान दिया गया है कि हर स्थान पर सभी बच्चे स्कूल-पूर्व शिक्षा सहित पूर्ण स्कूल शिक्षा प्राप्त और पूरी कर सकें यह सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है। विश्व बैंक ने पाया कि स्कूल-पूर्व शिक्षा पर व्यय किया गया प्रत्येक डॉलर अधिक स्वस्थ और अधिक उत्पादक कार्यबल के रूप में 6 डॉलर से 17 डॉलर तक का सार्वजनिक लाभ कमाता है।³² घाना ने अपनी शिक्षा प्रणाली में अब दो वर्ष की स्कूल-पूर्व शिक्षा को शामिल किया है। चीन सभी बच्चों को स्कूल-पूर्व शिक्षा प्रदान करने पर विचार कर रहा है।³³

युवाओं को सशक्त बनाने के लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर कार्य करने की आवश्यकता है। राजनीतिक मोर्चे पर कम से कम 30 देशों में राष्ट्रीय स्तर पर या शहरों में, गांवों में या स्कूलों में, किसी न किसी प्रकार की अवयस्क संसदीय संरचना हैं।³⁴ इस प्रकार भागीदारी के विभिन्न रूपों में – सरकार प्रायोजित परामर्शदात्री भूमिकाओं में, युवा संसदों और गोलमेज परिचर्चाओं में – युवाओं के अभिमतों को नीति निर्माण में समाहित किया जा रहा है।

आर्थिक मोर्चे पर युवाओं के लिए नए अवसरों के निर्माण की और उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक कौशलों के साथ युवाओं को तैयार करने की आवश्यकता है। आज की अर्थव्यवस्था में जो कौशल महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं, उनमें से एक-तिहाई से अधिक 2020 तक बदल जाएंगे।³⁵ 21वीं सदी के लिए

चूंकि आधी मानव जाति मानव विकास की प्रगति का लाभ नहीं ले पा रही है, इसलिए ऐसा विकास सार्वभौमिक नहीं है

चित्रांकन 6

21वीं सदी के कौशल

सोचने के तरीके	कार्य के साधन	कार्य करने के तरीके	विश्व में जीने के कौशल
सृजनशीलता आलोचनात्मक सोच समस्या समाधान निर्णयशीलता सीखना	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सूचना साक्षरता	संचार सहकार्य	नागरिकता जीवन और आजीविका व्यक्तिगत और सामाजिक उत्तरदायित्व

स्रोत : मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय

कौशल हासिल करने को अंग्रेजी के 'सी' अक्षर से आरंभ होने वाली चार प्रवीणताओं – क्रिटिकल थिंकिंग (विवेचनात्मक सोच), कोलेबोरेटिंग (सहकार्य), क्रिएटिंग (सृजनशीलता) और कम्युनिकेटिंग (संचार) – का अंग बनाना होगा (चित्रांकन 6)।

अधिक आयु के लोगों और अशक्त लोगों के लिए प्रमुख उपायों में शामिल हैं : सार्वजनिक और निजी संयोजन में बुजुर्ग देखभाल की व्यवस्थाओं की स्थापना करना, मूलभूत गैर-अंशदायी सामाजिक पेंशनों के माध्यम से अधिक आयु के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना (जैसा कि ब्राजील में किया गया है)³⁶ और बुजुर्ग लोगों के लिए बच्चों को पढ़ाने, देखभाल के कार्य तथा स्वैच्छिक कार्य सहित ऐसे अवसरों का निर्माण करना जिनमें वे योगदान दे सकें।

मानव विकास प्राथमिकताओं के लिए संसाधन जुटाना

मानव विकास प्राथमिकताओं के लिए संसाधन जुटाने के विकल्पों में राजकोषीय स्थान निर्मित करने से लेकर जलवायु वित्त तक और निर्धन लोगों के लिये लाभरहित आर्थिक सहायताओं में कटौती करने से लेकर संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग तक शामिल हैं।

राजकोषीय स्थान के चार स्तंभ हैं – शासकीय विकास सहायता, घरेलू राजस्व, घाटे की वित्तीय भरपाई (घरेलू और बाहरी उधारी के माध्यम से) और परिव्यय प्राथमिकताओं और दक्षता में भिन्नताएं। राजकोषीय स्थान को बढ़ाने या पुनर्निर्मित करने के लिए किस स्तंभ का उपयोग किया जाए, इसका चुनाव मुख्यतः देश की

अपनी विशेषताओं या चारित्रिकताओं पर निर्भर करता है। 2009 में घाना ने स्वास्थ्य का बजट बढ़ाने के लिए राजस्व संग्रह में सुधार लाने पर विचार किया, सरकार के कुल बजट आवंटन में स्वास्थ्य का अंश स्थिर होते हुए भी उसने ऐसा किया था।³⁷

विप्रेषित धन को संगठित और सुव्यवस्थित करके उसे मानव विकास प्राथमिकताओं के निधियन का स्रोत बनाया जा सकता है। बांग्लादेश, जोर्डन और फिलीपींस जैसे देशों में, जहां इस धन का प्रवाह विशाल मात्रा में होता है, विप्रेषित धन बैंकों की स्थापना की जा सकती है। मेजबान देशों के साथ विचार-विमर्श करके विप्रेषित धन भेजने की सरल और पारदर्शी विधिक व्यवस्थाएं बनाई और स्थापित जा सकती हैं।

सबसे कम विकसित देशों में, जहां उत्सर्जन कम है, जलवायु वित्त जलवायु के प्रति लोचदार आजीविकाओं को बढ़ा सकता है, जल और स्वच्छता प्रणालियों में सुधार ला सकता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। ये निवेश संकीर्ण अर्थ में जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमों से आगे जाते हैं और अर्थव्यवस्थाओं तथा समाजों का दीर्घकालिक जलवायु लचीलापन बढ़ाकर मानव विकास अर्जित करने पर अधिक ध्यान देते हैं।

जीवाश्म ईंधनों के लिए अनुदानों को समाप्त करके संसाधनों को मानव विकास के लिए मुक्त किया जा सकता है। और संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग अतिरिक्त संसाधन उत्पन्न करने बराबर है। उदाहरण के लिए, टेलीमेडिसिन या दूरचिकित्सा इस बात का ध्यान रखे बगैर कि मरीज किस स्थान पर हैं, उन्हें चिकित्सा परामर्श और उपचार विकल्प प्रदान कर सकती है – और सेवा प्रदान करने की लागत में कमी ला सकती है।

मानव विकास प्राथमिकताओं के लिए संसाधन जुटाने के विकल्पों में राजकोषीय स्थान निर्मित करने से लेकर जलवायु वित्त तक और निर्धन लोगों के लिये लाभरहित आर्थिक सहायताओं में कटौती करने से लेकर संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग तक शामिल हैं

विशेष आवश्यकता वाले समूहों के लिए उपाय करना

चूंकि कतिपय सामाजिक समूहों (जातीय अल्पसंख्यक, मूल देशज लोग, अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्ति अथवा दिव्यांग) के विरुद्ध व्यवस्थित रूप से भेदभाव होता है

और इसके कारण वे पीछे छूट जाते हैं, इसलिए विशेष उपायों की आवश्यकता है ताकि वे मानव विकास में न्यायोचित परिणाम हासिल कर सकें।

सकारात्मक कार्रवाई का उपयोग करना

ऐतिहासिक और दीर्घस्थायी समूह की असमानताओं और समूह के भेदभावों को दूर करने में सकारात्मक कार्रवाई महत्वपूर्ण रही है। यह कार्रवाई तृतीयक शिक्षा में जातीय अल्पसंख्यकों के लिए नामांकन कोटे के रूप में या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अनुदान-प्राप्त ऋण हासिल करने में महिला उद्यमियों को वरीयता देने के रूप में हो सकती है।

सकारात्मक कार्रवाई के बल पर संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में भी अंतर आया है। 1995 में संयुक्त राष्ट्र चौथे विश्व सम्मेलन में बीजिंग घोषणापत्र और प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन के पश्चात कुछ देशों ने महिलाओं की सीटों के अनुपात में बढ़ोतरी के लिए लैंगिक कोटा अपनाया और इस प्रकार महिलाओं को निर्वाचित पदों के लिए खड़े होने और जीतने का आत्मविश्वास और प्रोत्साहन प्रदान किया। रवांडा इसका उज्ज्वल उदाहरण है, जहां हाउस ऑफ डिप्टीज में महिलाओं का 64 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है।³⁸

उपेक्षित समूहों के लिए मानव विकास को बढ़ावा देना

पहचानों और आवश्यकताओं में भारी विविधता के होते हुए भी उपेक्षित कर दिए गए समूह, जैसे जातीय अल्पसंख्यक, मूल देशज लोग, अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्ति, एचआईवी और एड्स के साथ रह रहे लोग और महिला समलैंगिक, पुरुष समलैंगिक, उभयलैंगिक, लिंगपरिवर्तित और अंतरयौन व्यक्ति प्रायः भेदभाव, सामाजिक कलंक और हानि पहुंचाए जाने के जोखिम जैसी बाध्यताओं का सामना करते हैं। किंतु इनमें से प्रत्येक समूह की अपनी विशेष आवश्यकताएं हैं और यदि उन्हें मानव विकास की प्रगति का लाभ उठाना है तो इन आवश्यकताओं को पूरा करना ही होगा।

जातीय अल्पसंख्यकों और अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों जैसे कुछ वध्य और कमजोर समूहों के लिए संविधानों में और अन्य विधि-विधानों में भेदभाव-विरोधी तथा अन्य अधिकारों की गारंटी दी गई है। इसी प्रकार, विशेष प्रावधान प्रायः मूल देशज लोगों की रक्षा करते हैं, जैसा कि कनाडा और न्यूजीलैंड में है।³⁹ तो भी कई मामलों में क्रियान्वयन और विधि के समक्ष पूर्ण समानता

के लिए प्रभावी तंत्रों का अभाव है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या विशिष्ट समूहों के लिए आयोग निगरानी प्रदान कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इन समूहों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। और महिला समलैंगिक, पुरुष समलैंगिक, उभयलैंगिक, लिंगपरिवर्तित और अंतरयौन समुदायों के सदस्यों को भेदभावों और दुर्व्यवहारों से उबारने के लिए एक विधिक ढांचे की आवश्यकता है जो उनके मानव अधिकारों का बचाव कर सके।

साधनहीन समूहों के जीवन को गढ़ने वाली प्रक्रियाओं में भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, संसदों में जातीय अल्पसंख्यकों के लिए कोटा और मूल देशज लोगों का प्रतिनिधित्व ऐसे तरीके हैं जिनसे उन्हें अपनी आवाज उठाने में मदद मिल सकती है। कुछ मूल देशज लोगों की अपनी संसदें या परिषदें हैं, जो परामर्शदात्री निकाय हैं। राष्ट्रीय विधायिका में मूल देशज प्रतिनिधित्व का सबसे लंबा इतिहास न्यूजीलैंड का है।⁴⁰

अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए समावेशन और समायोजन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं ताकि उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने, रोजगार पाने और समाज में अपना योगदान देने के लिए सशक्त किया जा सके। उनके कौशलों का विकास करने के लिए विशिष्ट व्यवसायगत प्रशिक्षण की पहल की जानी चाहिए। उत्पादक संसाधनों तक पहुंच बढ़ाकर, जैसे स्व-रोजगार के लिए वित्त, और मोबाइल उपकरणों पर जानकारी प्रदान करके स्व-रोजगार में मदद पहुंचाई जा सकती है। प्रौद्योगिकी सहित उपयुक्त अवसंरचना अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को अधिक गतिशील होने में समर्थ बना सकती है।

प्रवासी और शरणार्थी मेजबान देशों में कमजोर और वध्य स्थिति में है तथा प्रवास और इसके नए घटनाक्रम को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता है। देशों को ऐसे कानून पारित करने चाहिए, जो शरणार्थियों की, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की, जो शरणार्थी जनसंख्या का बड़ा भाग और मुख्य पीढ़ित हैं, उनकी रक्षा कर सकें। विस्थापितों, जैसे स्कूलों में पढ़ रहे शरणार्थी बच्चों, की जरूरतों के लिए पारगमन तथा गंतव्य देशों को अनिवार्य सार्वजनिक वस्तुएं प्रदान करनी चाहिए। और गंतव्य देशों को शरणार्थियों के लिए अस्थायी कार्य नीतियां और प्रावधान प्रतिपादित करने चाहिए।

उपेक्षित समूह प्रायः इसी प्रकार की बाध्यताओं का सामना करते हैं। किंतु इनमें से प्रत्येक समूह की अपनी विशेष आवश्यकताएं हैं और यदि उन्हें मानव विकास की प्रगति का लाभ उठाना है तो इन आवश्यकताओं को पूरा करना ही होगा

मानव विकास को लोचदार बनाना

वैश्विक महामारियों, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं, हिंसा और टकरावों जैसे आघातों का खतरा उत्पन्न होने पर मानव विकास की प्रगति प्रायः अवरुद्ध या छिन्न-भिन्न हो जाती है। वध्य और उपेक्षित लोग इससे सर्वाधिक पीड़ित होते हैं।

महामारियों, आघातों और जोखिमों को संबोधित करना

एंटीरेट्रोवाइरल उपचारों को उन्नत बनाने में काफी प्रगति हुई है, किंतु यह एचआईवी के साथ रह रहे 18 मिलियन लोगों को अब भी सुलभ नहीं है।⁴¹ इनमें युवा

महिलाएं, जो लैंगिकता आधारित हिंसा का सामना कर रही हो सकती हैं और जानकारी तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक जिनकी सीमित पहुंच है, सर्वाधिक अनावृत हैं, उसी प्रकार जैसे बंदी, यौन कार्यकर्ता, मादक पदार्थ लेने वाले और लिंगपरिवर्तित लोग भी हैं। तब भी, महिलाओं और बच्चों में संक्रमण की दरों को कम करने में और उपचारों तक उनकी पहुंच बढ़ाने में सफलताएं मिली हैं।

निरंतर अधिकाधिक अंतर्संबद्ध होते जा रहे विश्व में संभावित स्वास्थ्य संकटों के लिए तैयार रहना एक प्राथमिकता बन गई है। हाल ही में जीका वायरस की महामारी इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। देशों ने जीका वायरस के फैलने पर भिन्न-भिन्न ढंग से प्रतिक्रिया की। वायरस संक्रमण से पहले ही गुजर रहे देशों, जैसे कोलंबिया, दि डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर और जमैका, ने महिलाओं को गर्भधारण स्थगित करने की सलाह दी।⁴² ब्राजील में जीका वायरस से लड़ने के प्रयास में मच्छर की एक नई नस्ल विमुक्त की गई और लोगों को मच्छर नियंत्रण के कार्य में शिक्षित करने के लिए और उन्हें इस वायरस से जुड़े जोखिमों के प्रति सावधान करने के लिए सशस्त्र बलों के सदस्यों को देश भर में भेजा गया।⁴³

अभी और भी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 60 से अधिक भागीदारों के साथ मिलकर संशोधित रणनीतिक प्रतिक्रिया योजना तैयार की है, जो अनुसंधान, पहचान, रोकथाम और देखभाल तथा सहायता पर ध्यान देती है।⁴⁴

नीतियों और कार्यक्रमों में सभी स्तरों पर आपदाओं के प्रति लचीलापन निर्मित करके विशेष रूप से लोगों के लिए आपदाओं के जोखिमों को कम और प्रभावों का शमन किया जा सकता है। आपदा जोखिम घटाव पर 2015 के तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन के उपरांत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित आपदा जोखिम घटाव के लिए सेनडई रूपरेखा के केंद्र में नवाचारी कार्यक्रम हैं।

हिंसा का प्रतिकार करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना

हिंसा के संचालक तत्व जटिल हैं और इसलिए बहुसूत्रीय तरीके की मांग करते हैं जिसमें शामिल हैं : निष्पक्षता और हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता पर आधारित विधि के शासन को बढ़ावा देना, हिंसा के ज्वलंत स्थलों पर स्थानीय सरकारों, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था और कानून लागू करने वाले कर्मियों को सुदृढ़ करना, और हिंसा तथा उसके पीड़ितों को संबोधित करने के लिए प्रत्युत्तर तथा सहायता सेवाएं विकसित करना।

व्यवहार्य नीति विकल्पों में शामिल हैं : उच्च गुणवत्ता के आधारभूत ढांचे का विकास करना, अत्यधिक अपराध वाले पास-पड़ोस में सार्वजनिक पारगमन में सुधार लाना, शहरों के निर्धनतम क्षेत्रों में बेहतर आवासों का निर्माण करना और विशेष रूप से युवा लोगों को

सामाजिक सामंजस्य को सुदृढ़ बनाने से जोड़कर हिंसा के सामाजिक-आर्थिक विकल्प प्रदान करना।

टकराव के बाद की स्थितियों में मानव कुशलता बनाए रखना

राजनीतिक मोर्चे पर संस्थाओं का रूपांतरण कुंजी है। यह सामुदायिक पुलिस व्यवस्थाओं, त्वरित सरकारी कार्रवाइयों (जैसे अधिक तेज गति से प्रकरणों की प्रक्रियाएं पूरी करना) और पूर्व लड़ाकों को निशस्त्र और अलग करते हुए उन्हें पुनः समाहित करने के माध्यम से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

आर्थिक मोर्चे पर आधारभूत सेवाओं को पुनर्जीवित करना, अनेक लक्ष्यों को समाहित करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यों की सहायता करना, लोक निर्माण कार्यक्रमों को आरंभ करना और लक्ष्यबद्ध समुदाय-आधारित कार्यक्रमों (जैसे कामचलाऊ स्कूल ताकि बच्चे स्कूल की सुलभता से वंचित न हों) का प्रतिपादन तथा क्रियान्वयन करना निरंतर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की कुंजी है।

जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना

जलवायु परिवर्तन निर्धन तथा उपेक्षित लोगों के जीवन और आजीविकाओं को खतरे में डालता है। इसे संबोधित करने के लिए तीन आरंभिक नीतिगत उपायों की आवश्यकता है। कार्बन प्रदूषण पर शुल्क लगाना – उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था या कार्बन-कर के माध्यम से – उत्सर्जन में कमी लाता है और निवेशों को स्वच्छतर विकल्पों की ओर ले जाता है। लगभग 40 देश और 20 से अधिक शहर, राज्य और प्रांत कार्बन पर शुल्क लगाने के उपाय का प्रयोग करते हैं।⁴⁵

ईंधन पर कर लगाना, जीवाश्म ईंधन पर आर्थिक सहायताओं को हटाना और "कार्बन की सामाजिक लागत" के विनियमों को समाविष्ट करना कार्बन पर सटीक रूप से शुल्क लगाने के अधिक सीधे तरीके हैं। हानिकारक जीवाश्म ईंधन के अनुदानों को चरणबद्ध ढंग से हटाकर देश अपनी इन धनराशियों को वहां व्यय कर सकते हैं जहां वे सर्वाधिक आवश्यक और सर्वाधिक प्रभावी हैं जिनमें निर्धन लोगों की लक्ष्यबद्ध सहायता भी शामिल है।

सही शुल्क लगाना समीकरण का केवल एक भाग है। विशेषकर विकासशील देशों में शहर तेजी से बढ़ रहे हैं। परिवहन और भू उपयोग का सावधानीपूर्ण नियोजन करके और ऊर्जा दक्ष मानकों की स्थापना करके शहर असंवहनीय विन्यासों में अवरुद्ध होने से बच सकते हैं। वे वायु प्रदूषण में कमी लाते हुए निर्धन लोगों के लिए नौकरियों और अवसरों की सुलभता को भी खोल सकते हैं।

ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय या अक्षत ऊर्जा को बढ़ाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी के लिए सतत ऊर्जा पहल 2030 के लिए तीन लक्ष्य निर्धारित करती है :

आघातों का खतरा उत्पन्न होने पर मानव विकास की प्रगति प्रायः अवरुद्ध या छिन्न-भिन्न हो जाती है। वध्य और उपेक्षित लोग इससे सर्वाधिक पीड़ित होते हैं।

आधुनिक ऊर्जा की सार्वभौम सुलभता अर्जित करें, ऊर्जा दक्षता में सुधार की दर को दोगुना करें और वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा के अंश को दोगुना करें। कई देशों में विकसित की जा रही उपयोगिता स्तर की नवीकरणीय ऊर्जा अब जीवाश्म ईंधन संयंत्रों से अधिक सस्ती है या उनके बराबर मूल्य की है।⁴⁶

जलवायु के अनुकूल चतुराईपूर्ण कृषि तकनीकों किसानों की उत्पादकता और जलवायु परिवर्तन पर प्रभावों का लचीलापन बढ़ाने में उनकी मदद करती है, वहीं कार्बन सिंक बनाती हैं जो विशुद्ध उत्सर्जन कम करते हैं। वन, जो विश्व के फेफड़े हैं, कार्बन को सोख लेते हैं और उसे मिट्टी, वृक्षों और पर्णसमूहों में जमा करके रखते हैं।

गरीबी-पर्यावरण के गठजोड़ पर भी ध्यान देना आवश्यक है, जो जटिल है, किंतु हाशियों पर धकेल दिए लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण को हुई क्षति का दंश निर्धन लोगों को सहना पड़ता है, जबकि वे मुश्किल से ही इसका कारण होते हैं। समुदाय की साझा चीजों (जैसे साझा वन) की रक्षा करने वाली नीतियां निर्धन लोगों के अधिकार और पात्रताएं सुनिश्चित करती हैं और निर्धन लोगों को अक्षत ऊर्जा उपलब्ध करवाती हैं। इनसे जैवविविधता भी उन्नत होगी, जिस पर निर्धन लोगों का जीवन निर्भर है, और निर्धनता तथा पर्यावरण क्षति की नीचे की ओर सर्पिल गति भी उलटेगी।

सामाजिक रक्षाकवच को बढ़ावा देना

उपेक्षित समूहों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के नीतिगत विकल्पों में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को जारी रखना, सामाजिक सुरक्षा को उपयुक्त रोजगार रणनीतियों से जोड़ना और जीवनयापन की आय उपलब्ध करवाना शामिल है।

सामाजिक सुरक्षा का फलक हर एक के लिए न्यूनतम स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन तथा अन्य सामाजिक अधिकार सुरक्षित कर सकता है। लोक कार्यों के कार्यक्रम के माध्यम से नौकरियों का सृजन आय सृजित करने के माध्यम से निर्धनता को कम कर सकता है, भौतिक अवसंरचना का निर्माण कर सकता है और आघातों से निर्धन लोगों की रक्षा कर सकता है। बांग्लादेश में सार्वजनिक परिसंपत्ति के लिए ग्रामीण रोजगार अवसर कार्यक्रम इसका प्रमुख उदाहरण है।⁴⁷

नागरिकों के लिए नौकरियों के बाजार से स्वतंत्र गारंटी प्राप्त आधारभूत आय भी एक नीतिगत विकल्प है जिसका देश (जैसे फिनलैंड⁴⁸) विशेष रूप से साधनहीन वंचित समूहों के लिए सामाजिक सुरक्षा के एक उपकरण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं।

छूट गए लोगों को सशक्त बनाना

यदि नीतियां उपेक्षित और कमजोर लोगों को सकृशलता प्रदान नहीं करती हैं और यदि संस्थाएं यह सुनिश्चित नहीं कर पाती हैं कि लोग छूटे नहीं, तो ऐसे उपकरण और निवारण तंत्र होने ही चाहिए जिनसे ये लोग अपने अधिकारों का दावा कर सकें। उन्हें मानव अधिकारों की पुष्टि करके, न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करके, समावेशन को बढ़ावा देकर और उत्तरदायिता सुनिश्चित करके सशक्त बनाना होता है।

मानव अधिकारों की पुष्टि करना

सभी के लिए मानव विकास सुदृढ़ राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की मांग करता है जो भेदभाव को संबोधित करने और मानव अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता, जनादेश और इच्छाशक्ति से युक्त हों। मानवाधिकार आयोग और लोकपाल अधिकारों के दुरुपयोग की शिकायतों का निवारण करता है, सिविल समाजों और राज्यों को मानवाधिकारों के बारे में शिक्षित करता है और विधिक सुधारों की अनुशंसा करता है।

किंतु इन अधिकारों को कायम रखने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धताएं भिन्न-भिन्न हैं, राष्ट्रीय संस्थाओं के पास क्रियान्वयन की क्षमताएं अलग-अलग हैं और कभी-कभी उत्तरदायिता के तंत्र भी अनुपस्थित हैं। सांस्थानिक कमियों की बात छोड़ भी दें, तो विकास को मानव अधिकार के रूप में बरतना कुछ आयामों

और संदर्भों में अभावों और वंचनाओं को कम करने में सहायक रहा है।

एकीकृत विश्व में उत्तरदायिता के राज्य-केंद्रित मॉडल का विस्तार राज्येतर कर्ताओं के दायित्वों तक और राष्ट्रीय सीमाओं से आगे राज्य के दायित्वों तक किया ही जाना चाहिए। सुस्थापित घरेलू तंत्रों और अधिक मजबूत अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई के बिना सार्वभौमिक रूप से मानव अधिकारों को साकार नहीं किया जा सकता।

न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना

न्याय तक पहुंच लोगों की वह क्षमता है जिससे वे औपचारिक और अनौपचारिक न्यायिक संस्थाओं के माध्यम से उपचार पाने की चेष्टा करते और पाते हैं।

निर्धन और साधनहीन लोगों को भीषण बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें उनकी जागरूकता और विधिक ज्ञान का अभाव भी शामिल है, जो ढांचागत और व्यक्तिगत अलगाव से और भी बढ़ जाता है। निर्धन लोग जन सेवाओं तक पर्याप्त पहुंच से वंचित हैं, जो प्रायः महंगी और जटिल हैं और बहुत कम संसाधनों, कर्मियों और सुविधाओं के बल पर चलाई जाती हैं। सुदूर क्षेत्रों में पुलिस थाने और न्यायालय उपलब्ध नहीं हो सकते हैं और निर्धन लोग दुर्लभ रूप से ही विधिक प्रक्रिया की लागत वहन कर पाते हैं। अदर्श-न्यायिक तंत्र भी पहुंच से बाहर या पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकते हैं।

मूल देशज लोगों को और नस्लीय तथा जातीय अल्पसंख्यकों को न्याय मिलने की बाधाएं उनकी ऐतिहासिक अधीनस्थ स्थिति और उस सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था से उत्पन्न हुई हैं जो विधिक ढांचे और न्यायिक प्रणाली में पक्षपात और पूर्वाग्रह को बल देती हैं।

समावेशन को बढ़ावा देना

हर एक के लिए मानव विकास, विकास के विमर्श और प्रक्रिया में सभी के समावेशन की मांग करता है।

प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया ने संगठन और संचार के नए वैश्विक रूपों और तरीकों की सुगमता प्रदान की है। उन्होंने आधुनिक सक्रियतावाद को एकजुट किया है और साइबर सक्रियतावाद के माध्यम से लोगों तथा समूहों को अपने अभिमत व्यक्त करने का अवसर दिया है। सार्वजनिक संस्थाओं में नागरिकों की भागीदारी की गुणवत्ता और अवसर को बढ़ाने में नागरिक शिक्षा, क्षमता का विकास और राजनीतिक संवाद अंतर्भूत है।

उत्तरदायिता सुनिश्चित करना

मानव विकास हर एक तक पहुंचे, विशेष रूप से बाहर रह गए लोगों के अधिकारों की रक्षा हो, यह सुनिश्चित करने में उत्तरदायिता का केंद्रीय महत्व है।

सामाजिक संस्थाओं की उत्तरदायिता सुनिश्चित करने का एक बड़ा साधन सूचना का अधिकार है। 1990 के दशक से ही 50 से अधिक देशों ने प्रायः लोकतांत्रिक परिवर्तनों और सार्वजनिक जीवन में सिविल सोसायटी संगठनों की सक्रिय भागीदारी के कारण ऐसे साधन अपनाए हैं जो सूचना के अधिकार की रक्षा करते हैं।⁴⁹

सूचना का अधिकार सार्वजनिक अभिमत के निर्माण में उस सूचना के उपयोग की, सरकारों से हिसाब मांगने की, निर्णय लेने में भागीदारी की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग की स्वतंत्रता की मांग करता है। उत्तरदायिता सुनिश्चित करने में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है।

राज्य संस्थाओं को उत्तरदायी ठहराने के सहभागी प्रयासों, जैसे सार्वजनिक व्यय का पता लगाने वाले सर्वे, सिटिजन रिपोर्ट कार्ड, स्कोर कार्ड, सामाजिक लेखापरीक्षण और सामुदायिक निगरानी, इन सबका सेवा के उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच सीधे उत्तरदायिता के संबंध विकसित करने के लिए उपयोग किया गया है।

वैश्विक सांस्थानिक सुधार और अधिक निष्पक्ष बहुपक्षीय व्यवस्था हर एक के लिए मानव विकास प्राप्त करने में सहायक होगी

हम एक वैश्वीकृत विश्व में रहते हैं जहां मानव विकास के परिणाम न केवल राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाइयों से निर्धारित होते हैं, बल्कि वैश्विक स्तर के ढांचों, घटनाओं और कार्यों से भी निर्धारित होते हैं। वैश्विक व्यवस्था के वर्तमान स्थापत्य की कमियां मानव विकास के लिए तीन मोर्चों पर चुनौतियां उपस्थित करती हैं। अन्यायपूर्ण वैश्वीकरण के वितरण से जुड़े परिणामों ने जनसंख्या के कुछ वर्गों की प्रगति को बढ़ाया है, जबकि निर्धन और वध्य लोगों को बाहर छोड़ दिया है। वैश्वीकरण बाहर छोड़ दिए गए लोगों को आर्थिक रूप से असुरक्षित भी बना रहा है। और लोग लंबे समय से चले आ रहे टकरावों का कष्ट सह रहे हैं। संक्षेप में, ये सब राष्ट्रीय प्रयासों को क्षीण करते हैं और हर एक के लिए मानव विकास में बाधाएं खड़ी करते हैं।

वैश्विक संस्थागत सुधारों में वैश्विक बाजारों के विनियमन के व्यापकतर क्षेत्रों, बहुपक्षीय संस्थाओं की शासन व्यवस्था और वैश्विक सिविल सोसायटी को सुदृढ़ करना भी समाहित होना चाहिए। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र विशिष्ट कार्रवाई प्रतिबिंबित करता है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिरता देना

सुधारों को मुद्रा के लेन-देन और पूंजी के प्रवाहों का विनियमन करने तथा दीर्घआर्थिक नीतियों और विनियमों का समन्वय करने पर ध्यान देना चाहिए। एक विकल्प सीमा-पार लेन-देनों पर बहुपक्षीय कर लगाना है, तो दूसरा विकल्प अलग-अलग देशों द्वारा पूंजी नियंत्रणों का उपयोग करना है।

निष्पक्ष व्यापार और निवेश नियमों को लागू करना

अंतरराष्ट्रीय एजेंडा यह होना चाहिए कि वस्तुओं, सेवाओं और ज्ञान के व्यापार का विस्तार करने के नियमों को मानव विकास और सतत विकास लक्ष्यों की सहायता के अनुरूप निर्धारित किया जाए। इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख सुधारों में शामिल हैं : विश्व व्यापार संगठन की दोहा वार्ताओं को अंतिम रूप देना, वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था में सुधार लाना और वैश्विक निवेश रक्षा व्यवस्था में सुधार करना।

वैश्विक संस्थागत सुधारों में वैश्विक बाजारों के विनियमन के व्यापकतर क्षेत्रों, बहुपक्षीय संस्थाओं की शासन व्यवस्था और वैश्विक सिविल सोसायटी को सुदृढ़ करना भी समाहित होना चाहिए

प्रवासन की निष्पक्ष व्यवस्था अपनाना

ऐसे उपाय करने की आवश्यकता है जो प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा करने तथा उनके लिए अवसरों को बढ़ावा देने की रणनीतियों को सुदृढ़ करें, आर्थिक (स्वैच्छिक) प्रवासन का समन्वय करने के वैश्विक तंत्र की स्थापना करें और बलपूर्वक विस्थापित किए गए लोगों के लिए गारंटी के साथ शरण प्राप्त करना सुगम बनाए। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सितंबर 2016 में शामिल हुआ और इसके कार्यों में विस्तार और प्रगति होना अपेक्षित है।

बहुपक्षीय संस्थाओं की अधिक निष्पक्षता तथा वैधता के प्रति आश्वस्त करना

बहुपक्षीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता और उत्तरदायिता का परीक्षण करने का समय अब आ गया है। इन संस्थाओं को अधिक निष्पक्षता और वैधता की ओर ले जाने के लिए कुछ नीतिगत विकल्प हैं : बहुपक्षीय संगठनों में विकासशील देशों की आवाज को बढ़ाना, बहुपक्षीय संगठनों के प्रमुखों की नियुक्ति में पारदर्शिता को बेहतर बनाना और जन-केंद्रित लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए समन्वय तथा प्रभावशीलता बढ़ाना।

वैश्विक रूप से करों का समन्वयन तथा वित्त की निगरानी करना

वैश्विक स्वचालित सूचना विनिमय की दिशा में कदम बढ़ाकर टैक्स या कर लगाने के कार्यों में तथा विनियामक प्राधिकारियों द्वारा आय पर दृष्टि रखने और अवैध वित्तीय प्रवाहों का पता लगाने में सुगमता प्रदान की जा सकती है, जिनका उपयोग फिर मानव विकास के लिए किया जा सकता है। इसके लिए देशों को अधिकाधिक तकनीकी क्षमता की आवश्यकता होगी ताकि वे सूचना को संसाधित तथा कर चोरी, कर अपवचन तथा अवैध प्रवाहों के विरुद्ध सक्रिय नीतियों को क्रियान्वित कर सकें।

वैश्विक अर्थव्यवस्था को सातत्यपूर्ण बनाना

वैश्विक कार्रवाइयों को राष्ट्रीय स्तर पर सातत्यपूर्ण विकास गतिविधियों का पूरक होना ही चाहिए। वैश्विक ऊष्णता को वश में करना संभव है। अतीत में समन्वित वैश्विक कार्रवाई सफल रही हैं, जैसा कि 1990 के दशक में ओजोन का छीजना रोकने के प्रयासों के साथ हुआ था। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने तथा पर्यावरण की रक्षा करने की जरूरत के लिए निरंतर अधिवक्ता तथा संचार की अनिवार्य आवश्यकता है ताकि विभिन्न हितधारकों (बहुपक्षीय विकास बैंकों सहित) का समर्थन जुटाया जा

सके। हाल ही में निर्मित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने सुस्पष्ट रूप से स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की वचनबद्धता व्यक्त की है।

निधियों से परिपूर्ण बहुपक्षवाद तथा सहयोग सुनिश्चित करना

बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय विकास बैंक वैश्वीकरण की अनेक चुनौतियों को संबोधित करने के लिए और अधिक कर सकते हैं। पारंपरिक दानदाताओं से आधिकारिक विकास सहायताओं को बढ़ाना, दक्षिण-दक्षिण तथा त्रिकोणीय सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों की भागीदारी का विस्तार करना और वित्तपोषण के नवाचारी विकल्पों का दोहन करना उपयोगी होगा।

जन सुरक्षा का वैश्विक रूप से बचाव करना

मानव विकास के दृष्टिकोण से मानवीय आपातस्थितियों तथा संकटों में सहायता एक नैतिक कर्तव्य है। ऐसे मामलों में प्रस्तावित समाधानों में शामिल हैं : आघातों के अल्पकालिक प्रत्युत्तरों के अतिरिक्त रोकथाम के वर्तमान तंत्रों को नए सिरे से गढ़ना, जमीनी कार्य संचालनों की प्राथमिकताएं निर्धारित करना और आंतरिक तथा बाह्य रूप से सिविल सोसायटी तथा निजी क्षेत्र के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना।

वैश्विक सिविल सोसायटी की अधिक तथा बेहतर भागीदारी को बढ़ावा देना

सिविल सोसायटी की क्षमता को बाहर निकालने के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं में उसके भाग लेने के तंत्रों का विस्तार करने, बहुपक्षीय संस्थाओं की पारदर्शिता और उत्तरदायिता को बढ़ाने, महिलाओं, युवाओं और जातीय अल्पसंख्यकों जैसे समूहों पर ध्यान देने वाले समावेशी वैश्विक सिविल समाज नेटवर्कों को बढ़ावा और समर्थन देने, सक्रिय पारदर्शिता तंत्रों के माध्यम से सूचना और ज्ञान के स्वतंत्र प्रवाह में बढ़ोतरी करने, तथा अंतरराष्ट्रीय खोजपरक पत्रकारों के काम की रक्षा करने की आवश्यकता है।

कार्य एजेंडा

हर एक के लिए मानव विकास सपना नहीं है, यह साकार किए जाने योग्य लक्ष्य है। हमने जो अर्जित किया है उस पर आगे निर्माण कर सकते हैं। हम चुनौतियों पर विजय पाने के लिए नई संभावनाओं का दोहन कर सकते हैं। हम वह प्राप्त कर सकते हैं जो कभी अप्राप्य जान पड़ता था, क्योंकि आज जो चुनौतियां प्रतीत होती हैं कल उन पर विजय प्राप्त की

जा सकती है। अपनी आशाओं को साकार करना हमारी पहुंच के भीतर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति महामहिम जुआन मैनुएल सांतोस और 2016 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एक शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व बनाने की आशाओं की पुष्टि करते हैं (विशेष लेख देखें)। एजेंडा 2030 और सतत विकास लक्ष्य हर एक के लिए मानव विकास की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम हैं। इसके विश्लेषण और निष्कर्षों को आगे बढ़ाते हुए यह रिपोर्ट हर एक के लिए मानव विकास सुनिश्चित करने के लिए पांच सूत्रीय कार्य एजेंडा प्रस्तावित करती है। कार्यों में नीतिगत मुद्दे और वैश्विक प्रतिबद्धताएं समाहित हैं।

मानव विकास में न्यूनताओं का सामना कर रहे लोगों की पहचान करना और पता लगाना कि वे कहाँ हैं

मानव विकास की प्रगति से पीछे छूट गए लोगों की पहचान करना और उनके स्थानों का मानचित्रण करना उपयोगी अधिवक्ता तथा प्रभावी नीति निर्माण के लिए अनिवार्य है। ऐसा मानचित्रण उपेक्षित और कमजोर लोगों की सकुशलता में सुधार लाने के लिए नीतियों के प्रतिपादन और क्रियान्वयन में कार्रवाई की मांग करने तथा नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन करने में विकास कार्यकर्ताओं की सहायता कर सकता है।

विभिन्न प्रकार के उपलब्ध नीतिगत विकल्पों का सामंजस्य के साथ अनुसरण करना

हर एक के लिए मानव विकास बहुकोणीय राष्ट्रीय नीतिगत विकल्पों की मांग करता है : सार्वभौम नीतियों का उपयोग करते हुए छूट गए लोगों तक पहुंचना, विशेष जरूरतों वाले समूहों के लिए उपाय करना, मानव विकास को लोचदार बनाना और छूट गए लोगों को सशक्त बनाना।

हर देश की परिस्थितियां भिन्न हैं, इसलिए नीतिगत विकल्पों को भी प्रत्येक देश के अनुसार ढालना होगा। प्रत्येक देश में नीतियों का अनुसरण हितधारकों को शामिल करने, स्थानीयता तथा उपराष्ट्रीयताओं के अनुकूल बनाने और आड़ी (सभी क्षेत्रों में) तथा खड़ी (अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक संगति के लिए) रेखाओं की सीध में लाने के माध्यम से सामंजस्यपूर्ण ढंग से करना होगा।

लैंगिक अंतर को पाटना

लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तीकरण मानव विकास के आधारभूत आयाम हैं। लैंगिक अंतर क्षमताओं में

तथा साथ ही अवसरों में विद्यमान हैं और आधी मानवता की पूर्ण क्षमता को साकार करने के लिए प्रगति बहुत धीमी है।

सितंबर 2015 में न्यू यॉर्क में एक ऐतिहासिक सम्मेलन में कोई 80 विश्व नेताओं ने 2030 तक महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने की वचनबद्धता व्यक्त की थी और त्वरित बदलावों को एक झटके से आरंभ करने के लिए मापने योग्य कार्रवाइयों की घोषणा की थी।⁶⁰ जो वचन और सहमतियां व्यक्त की गई थीं, उन पर कार्रवाई करने का समय अब आ गया है।

सतत विकास लक्ष्यों और अन्य वैश्विक समझौतों को क्रियान्वित करना

सतत विकास लक्ष्य अपने आप में तो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं ही, वे हर एक के लिए मानव विकास हासिल करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। एजेंडा 2030 और मानव विकास दृष्टिकोण परस्पर एक दूसरे पर बल देने वाले हैं। इतना ही नहीं, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना सभी मनुष्यों के लिए अपने जीवन की पूर्ण क्षमता को साकार करने की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

जलवायु परिवर्तन के संबंध में ऐतिहासिक पेरिस समझौता पहला है जो विकसित और विकासशील दोनों देशों को एक साझा रूपरेखा में लाता है और उन सभी से आने वाले वर्षों में अपने श्रेष्ठतम प्रयास करने तथा अपनी वचनबद्धताओं पर बल देने का आग्रह करता है। सितंबर 2016 में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन ने शरणार्थियों तथा प्रवासियों के सम्मुख उपस्थित मुद्दों को संबोधित करने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होने की साहसी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। अंतरराष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रीय सरकारों और अन्य सभी पक्षों को समझौतों का सम्मान, क्रियान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करना ही चाहिए।

वैश्विक व्यवस्था में सुधारों की दिशा में काम करना

अधिक निष्पक्ष वैश्विक व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने के लिए वैश्विक सांस्थानिक सुधारों के एजेंडे को वैश्विक बाजारों और उनके विनियमन पर, बहुपक्षीय संस्थाओं की शासन व्यवस्था पर और वैश्विक सिविल समाज को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान देना चाहिए। सार्वजनिक अधिवक्ता को बढ़ावा देकर, हितधारकों के बीच गठबंधन बनाकर और सुधार एजेंडे का मार्ग प्रशस्त करके सुधारों के इस एजेंडे का ओज और उत्साह के साथ लगातार समर्थन किया जाना चाहिए।

* * *

एजेंडा 2030 और सतत विकास लक्ष्य हर एक के लिये मानव विकास की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम हैं

कोलंबिया में शांति विश्व के लिए भी शांति है

कोलंबिया में लातीन अमेरिका के सबसे लंबे समय से चले आ रहे और एकमात्र बचे आंतरिक सशस्त्र टकराव को समाप्त करने के लिए हम पहले किसी भी समय से अधिक दृढ़संकल्प हैं।

कोलंबियाई नागरिक उस समझौते को लेकर बंटे हुए थे जो सरकार और एफ.ए.आर.सी. गुरिल्लों के बीच हुआ था। और इसलिए हमें एक नया शांति समझौता करने का प्रयास करना पड़ा, जो संदेहों को दूर कर देगा और राष्ट्रव्यापी समर्थन हासिल करेगा। लगभग साथ ही साथ हमने अंतिम बचे गुरिल्लों ई.एल.एन. के साथ शांति वार्ता आरंभ करने की घोषणा की। हम आशा करते हैं कि इससे हमारे देश में सशस्त्र टकराव निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे।

विगत पांच दशकों से कोलंबिया को युद्ध की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है और इसने निस्संदेह राष्ट्र की संभावनाओं को चोट पहुंचाई है। लॉस एंजीज यूनिवर्सिटी के अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि जो घर-परिवार बलात विस्थापन और हिंसा के शिकार हुए हैं, उनकी आय घटकर आधी रह गई है। स्थिति तब और विकट हो जाती है जब हम विचार करते हैं कि इन लोगों को उबरने में भी संभवतः कठिनाइयों का सामना करना होगा और ये अत्यंत गरीबी की स्थितियों में जीने के जोखिम से घिरे हैं।

हमारी अर्थव्यवस्था पर तो युद्ध का प्रभाव पड़ा ही है, उससे भी अधिक इसका सबसे तीव्र प्रभाव 2,50,000 या उससे भी अधिक मृतकों – और उनके परिवारों – और 8 मिलियन पीड़ितों तथा देश के भीतर ही विस्थापित हुए लोगों पर पड़ा है। प्रत्येक गंवाई गई जान, साथ ही सशस्त्र टकराव से प्रभावित और बच गए लोगों की एक-एक व्यक्तिगत और पारिवारिक त्रासदियां हमें उदास भी करती हैं और हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत भी करती हैं।

हम इस मानव विकास रिपोर्ट की भावना से सहमत हैं, जो यह है कि, समाज की समृद्धि की परख करते समय अर्थव्यवस्थाओं की संपन्नता से पहले “मानव जीवन की संपन्नता” का विचार करना ही चाहिए। इस अर्थ में हम समझते हैं कि कोलंबियाई नागरिकों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए शांति आधारभूत शर्त है। और मैं शांति की एक अधिक व्यापक अवधारणा का उल्लेख कर रहा हूँ जो टकराव के समापन के उस पार जाती है और सौहार्द तथा सकृशलता लाती है।

अपर्याप्त आय वाला एक परिवार शांति से नहीं रह पाता, न ही वह परिवार शांति से रह पाता है जिसे समुचित आवास या शिक्षा सुलभ नहीं है। यही कारण है कि हमने ऐसी आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है जो हर एक को लाभ पहुंचाए और सामाजिक अंतरों को कम करे।

हमने अभी तक जो प्रगति की है वह सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। कोलंबिया ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए जाने से पहले ही इन लक्ष्यों का समर्थन किया था और इनकी दिशा में कार्य आरंभ कर दिया था। वास्तव में इन लक्ष्यों को अपनी राष्ट्रीय विकास योजना में शामिल करने वाले हम पहले देश थे।

हमारे शीघ्र आरंभ किए प्रयासों की ही देन है कि हम निर्धारित समय से पहले ही अपने कार्यों के प्रतिफल हासिल कर पाए हैं। उदाहरण के लिए, पिछले पांच वर्षों में हमने चरम निर्धनता को लगभग आधा घटा

लिया है – 14.4 प्रतिशत से 7.9 प्रतिशत तक। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसके बल पर हम यदि और शीघ्र नहीं भी तो 2025 तक इसका पूर्ण उन्मूलन करने का विचार कर पा रहे हैं।

आंकड़ों से आगे इस छलांग का अर्थ यह है कि लाखों कोलंबियाई नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर हुई है। हमें इसका पूर्ण निश्चय है क्योंकि गरीबी के आय-आधारित पारंपरिक उपायों के साथ-साथ हमने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का प्रवर्तन किया है, जो अन्य परिवर्तनशील तत्वों का, जैसे जन सेवाओं तक पहुंच या पारिवारिक आवास का प्रकार का, आकलन करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज अधिक संख्या में कोलंबियाई नागरिक बेहतर जीवन जी रहे हैं।

एक और सतत विकास लक्ष्य – शिक्षा – की गुणवत्ता में भी हमने शीघ्र प्रगति की। न केवल सभी बच्चे और युवा पब्लिक स्कूलों में निशुल्क पढ़ रहे हैं बल्कि हम उनकी कक्षा के घंटों में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं और विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से सीखने की गुणवत्ता में भी सुधार ला रहे हैं। इन प्रयासों का परिणाम यह हुआ है कि हमारे छात्रों ने उनके ज्ञान और कौशलों को मापने वाली परीक्षाओं में औसत अंकों में यथेष्ट सुधार किया है।

शांति निर्माण पर हमारे ध्यान केंद्रित करने के साथ, शिक्षा पर बल देना इस बात का संभवतः सबसे अच्छा उदाहरण है कि सशस्त्र टकराव के बोझ से छुटकारा पाकर इस नए चरण में हम कितना कुछ कर सकते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि शिक्षा का बजट सुरक्षा और रक्षा के बजट से अधिक है, जो 2025 तक लातीन अमेरिका का सबसे शिक्षित देश बनने के हमारे लक्ष्य के अनुरूप है।

शांति, न्याय और शिक्षा तीन ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे कोलंबियाई नागरिक ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं। शांति, न्याय और शिक्षा पिछले पांच वर्षों से हमारे मुख्य प्रयासों के तीन स्तंभ हैं।

तथापि यदि हमारा लक्ष्य “हर एक के लिए मानव विकास” अर्जित करना है, तो हमारे प्रयास यहीं नहीं रुक सकते : जलवायु परिवर्तन मानव जाति के समक्ष उपस्थित अब तक का सबसे बड़ा खतरा है।

इस संबंध में कोलंबिया ने इस परिघटना से निपटने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का निर्णय लिया है। इस ग्रह पर सबसे अधिक जैवविविधतापूर्ण क्षेत्रों में से एक के रखवाले होने के नाते, असाधारण वनों, जल संसाधनों और मिट्टी की उर्वरता के साथ, हमारे कंधों पर कोलंबियाई नागरिकों और विश्व दोनों की विराट जिम्मेदारी है।

“हरित वृद्धि” की अवधारणा हमारे आर्थिक विकास मॉडल का अंग है और इसे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की मुख्याधारा में लाया गया है। हम पूर्णतः मानते हैं कि वृद्धि और पर्यावरणिक सातत्य एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे परामो (दलदली भूमि के पारिस्थितिकी तंत्र) का सीमांकन और संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा – जो 2018 तक, उरुग्वे से भी बड़े भूभाग, 19 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच जाएंगे – हमारे संकल्प का प्रमाण है।

जलवायु समझौते पर पेरिस समझौते के अंतर्गत कोलंबिया ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है : 2030 तक ग्रीनहाउस गैसों के अनुमानित उत्सर्जनों में 20 प्रतिशत तक कमी लाना। और इस महत्वाकांक्षी उद्देश्य को हासिल करने के लिए हमने निर्णायक कार्य पहले ही आरंभ कर दिया

विशेष लेख

है : हमने विभिन्न ईंधनों पर कार्बन कर लगाने के लिए एक विधेयक कांग्रेस में प्रस्तुत कर दिया है। हम पहले लातीन अमेरिकी देश – और विश्व के पहले देशों में से एक – होंगे, जो ऐसा एक उपाय लागू करेगा। इस एक पहल से हम अपेक्षा करते हैं कि पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में स्थापित हमारी वचनबद्धता का आधा हम पूरा कर लेंगे।

शांति – जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है, इसे सकशलता और सौहार्द के अधिक व्यापक अर्थ में समझें – भावी पीढ़ियों के लिए एक व्यवहार्य विश्व की संभावना के दरवाजे खोलती है, एक ऐसा विश्व जिसमें उनके अस्तित्व मात्र को वैश्विक ऊष्णता (ग्लोबल वार्मिंग) से खतरा नहीं होगा। हमें यह पुष्टि करते हुए गर्व है कि ये प्रयास – सशस्त्र टकराव की समाप्ति के अतिरिक्त उन्नत शिक्षा और संवर्धित न्याय – विश्व को एक योगदान हैं।

टकराव की समाप्ति के साथ विश्व भर के लोग कोलंबिया के प्राकृतिक आश्चर्यों और पर्यटन का आनंद ले सकते हैं, जो दशकों से प्रतिबंधित था – यहां तक कि स्वयं कोलंबियाई नागरिकों के लिए भी।

साथ ही विदेशी व्यावसायिक लोग उन क्षेत्रों और अंचलों में नए अवसर खोज सकते हैं जो पहले हिंसा के कारण निषिद्ध थे।

न्याय और निष्पक्षता के संदर्भ में हम मध्य वर्ग को मजबूत कर रहे हैं जो नए बाजारों की खोज में रहने वाले निवेशकों के लिए अवसर का निर्माण करेगा। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ हम एक नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं जो भविष्य में विश्व में कहीं भी अपने कौशलों और ज्ञान का प्रयोग कर सकेगी।

“हर एक के लिए मानव विकास” ऐसी प्रतिबद्धता है जो हमारे अपने देश से आगे जाती है और हम चाहते हैं कि हमारा काम दूसरे देशों के ऊपर भी प्रभाव डाले और वहां के नागरिकों के जीवन को भी समृद्ध करे। इसी प्रकार हम अनुभव करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समर्थन ने कोलंबियाई नागरिकों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। हम पूर्णतः मानते हैं कि हम, कोलंबियाई और गैर-कोलंबियाई नागरिक, एकजुटता और सहकार्य की भावना से एक साथ मिलकर कार्य करना जारी रखेंगे ताकि कोलंबिया के लिए शांति और शेष विश्व के भी शांति का निर्माण कर सकें।

हुआन मैनुएल सांतोस

कोलंबिया के राष्ट्रपति और 2016 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता

मानव विकास के दृष्टिकोण से हम ऐसा विश्व चाहते हैं जहां सभी मनुष्यों को अपने जीवन की पूर्ण क्षमता को साकार करने की स्वतंत्रता हो ताकि वे वह प्राप्त कर सकें जिसे अपने लिए मूल्यवान समझते हैं। अंतिम विश्लेषण में, विकास लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए है। लोगों और इस पृथ्वी ग्रह के बीच एक संतुलन की आवश्यकता है। और मानवता को शांति और समृद्धि के लिए अथक प्रयास करना होगा। मानव विकास इस बात को पहचानने और मानने की मांग करता है कि प्रत्येक

जीवन बराबर से मूल्यवान है और इस बात को भी कि हर एक के लिए मानव विकास उन लोगों से आरंभ होना ही चाहिए जो सबसे पीछे रह गए हैं।

2016 की मानव विकास रिपोर्ट इन मुद्दों के समाधान के लिए एक बौद्धिक योगदान है। हम दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि इन मुद्दों को हल कर लिए जाने के बाद ही हम सब एक साथ इस यात्रा के अंत पर पहुंचेंगे। और जब हम पीछे मुड़कर दृष्टि डालेंगे, तो हम देखेंगे कि कोई भी पीछे नहीं छूटा है।

मानव विकास सूचकांक

एचडीआई श्रेणी	मानव विकास सूचकांक	असमानता-समायोजित एचडीआई				लैंगिक विकास सूचकांक		लैंगिक असमानता सूचकांक		बहुआयामी निर्धनता सूचकांक	
	मान	मान	सकल हानि	एचडीआई श्रेणी से अंतर*	मान	समूह	मान	श्रेणी	मान	वर्ष तथा सर्वे	
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	मान	2006-2015	
अति उच्च मानव विकास											
1 नॉर्वे	0.949	0.898	5.4	0	0.993	1	0.053	6	
2 ऑस्ट्रेलिया	0.939	0.861	8.2	-1	0.978	1	0.120	24	
2 स्विट्जरलैंड	0.939	0.859	8.6	-4	0.974	2	0.040	1	
4 जर्मनी	0.926	0.859	7.2	-1	0.964	2	0.066	9	
5 डेनमार्क	0.925	0.858	7.2	-2	0.970	2	0.041	2	
5 सिंगापुर	0.925	0.985	1	0.068	11	
7 नीदरलैंड्स	0.924	0.861	6.9	2	0.946	3	0.044	3	
8 आयरलैंड	0.923	0.850	7.9	-2	0.976	1	0.127	26	
9 आइसलैंड	0.921	0.868	5.8	6	0.965	2	0.051	5	
10 कनाडा	0.920	0.839	8.9	-2	0.983	1	0.098	18	
10 संयुक्त राज्य अमेरिका	0.920	0.796	13.5	-10	0.993	1	0.203	43	
12 हांगकांग, चीन (एसएसआर)	0.917	0.964	2	
13 न्यूजीलैंड	0.915	0.963	2	0.158	34	
14 स्वीडन	0.913	0.851	6.7	3	0.997	1	0.048	4	
15 लिक्टेंस्टाइन	0.912	
16 यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन)	0.909	0.836	8.0	-1	0.964	2	0.131	28	
17 जापान	0.903	0.791	12.4	-8	0.970	2	0.116	21	
18 कोरिया गणराज्य	0.901	0.753	16.4	-19	0.929	3	0.067	10	
19 इसराइल	0.899	0.778	13.5	-11	0.973	2	0.103	20	
20 लक्जमबर्ग	0.898	0.827	8.0	1	0.966	2	0.075	13	
21 फ्रांस	0.897	0.813	9.4	-1	0.988	1	0.102	19	
22 बेल्जियम	0.896	0.821	8.3	2	0.978	1	0.073	12	
23 फिनलैंड	0.895	0.843	5.8	9	1.000	1	0.056	8	
24 ऑस्ट्रिया	0.893	0.815	8.7	3	0.957	2	0.078	14	
25 स्लोवेनिया	0.890	0.838	5.9	9	1.003	1	0.053	6	
26 इटली	0.887	0.784	11.5	-3	0.963	2	0.085	16	
27 स्पेन	0.884	0.791	10.5	1	0.974	2	0.081	15	
28 घेक गणराज्य	0.878	0.830	5.4	10	0.983	1	0.129	27	
29 ग्रीस	0.866	0.758	12.4	-6	0.957	2	0.119	23	
30 बुर्नेई दारुलसलाम	0.865	0.986	1	
30 एस्टोनिया	0.865	0.788	8.9	3	1.032	2	0.131	28	
32 अंडोरा	0.858	
33 साइप्रस	0.856	0.762	10.9	-2	0.979	1	0.116	21	
33 माल्डा	0.856	0.786	8.1	3	0.923	4	0.217	44	
33 कतर	0.856	0.991	1	0.542	127	
36 पोर्लैंड	0.855	0.774	9.5	2	1.006	1	0.137	30	
37 लिथुआनिया	0.848	0.759	10.5	0	1.032	2	0.121	25	
38 चिली	0.847	0.692	18.2	-12	0.966	2	0.322	65	
38 सऊदी अरब	0.847	0.882	5	0.257	50	
40 स्लोवाकिया	0.845	0.793	6.1	12	0.991	1	0.179	39	
41 पुर्तगाल	0.843	0.755	10.4	1	0.980	1	0.091	17	
42 संयुक्त अरब अमीरात	0.840	0.972	2	0.232	46	
43 हंगरी	0.836	0.771	7.8	6	0.988	1	0.252	49	
44 लातविया	0.830	0.742	10.6	-1	1.025	2	0.191	41	
45 अर्जेंटीना	0.827	0.698	15.6	-6	0.982	1	0.362	77	0.015*	2005 N	
45 क्रोएशिया	0.827	0.752	9.1	2	0.997	1	0.141	31	
47 बहरीन	0.824	0.970	2	0.233	48	
48 मॉन्टेनेग्रो	0.807	0.736	8.8	1	0.955	2	0.156	33	0.002	2013 M	
49 रूसी गणराज्य	0.804	0.725	9.8	1	1.016	1	0.271	52	
50 रोमानिया	0.802	0.714	11.1	0	0.990	1	0.339	72	
51 कुवैत	0.800	0.972	2	0.335	70	
उच्च मानव विकास											
52 बेलारूस	0.796	0.745	6.4	6	1.021	1	0.144	32	0.001	2005 M	
52 ओमान	0.796	0.927	3	0.281	54	
54 बारबाडोस	0.795	1.006	1	0.291	59	0.004†	2012 M	
54 उरुग्वे	0.795	0.670	15.7	-7	1.017	1	0.284	55	
56 बुल्गारिया	0.794	0.709	10.7	2	0.984	1	0.223	45	
56 कजाखस्तान	0.794	0.714	10.1	4	1.006	1	0.202	42	0.004	2010/2011 M	

एचडीआई श्रेणी	मानव विकास सूचकांक	असमानता-समायोजित एचडीआई			लैंगिक विकास सूचकांक		लैंगिक असमानता सूचकांक		बहुआयामी निर्धनता सूचकांक	
	मान	मान	सकल हानि	एचडीआई श्रेणी से अंतर ^a	मान	समूह ^b	मान	श्रेणी	मान	वर्ष तथा सर्वे ^c
एचडीआई श्रेणी	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	मान	2006-2015
58 बहामास	0.792	0.362	77
59 मलयेशिया	0.789	0.291	59
60 पलाउ	0.788
60 पनामा	0.788	0.614	22.0	-19	0.997	1	0.457	100
62 एंटीगुआ और बरबूडा	0.786
63 सेशेल्स	0.782
64 मॉरीशस	0.781	0.669	14.4	-4	0.954	2	0.380	82
65 ट्रिनिडाड और टोबैगो	0.780	0.661	15.3	-5	1.004	1	0.324	67	0.007 ^g	2006 M
66 कोस्टा रिका	0.776	0.628	19.1	-9	0.969	2	0.308	63
66 सर्बिया	0.776	0.689	11.2	3	0.969	2	0.185	40	0.002	2014 M
68 क्यूबा	0.775	0.946	3	0.304	62
69 ईरान इस्लामी गणराज्य	0.774	0.518	33.1	-40	0.862	5	0.509	118
70 जॉर्जिया	0.769	0.672	12.7	3	0.970	2	0.361	76	0.008	2005 M
71 तुर्की	0.767	0.645	15.9	-3	0.908	4	0.328	69
71 मेनेजुएला बोलिवेरियाई गणराज्य	0.767	0.618	19.4	-11	1.028	2	0.461	101
73 श्रीलंका	0.766	0.678	11.6	8	0.934	3	0.386	87
74 सेंट फिट्स और नेविस	0.765
75 अल्बानिया	0.764	0.661	13.5	4	0.959	2	0.267	51	0.005	2008/2009 D
76 लेबनान	0.763	0.603	21.0	-10	0.893	5	0.381	83
77 मेक्सिको	0.762	0.587	22.9	-12	0.951	2	0.345	73	0.024	2012 N
78 अजरबैजान	0.759	0.659	13.2	5	0.940	3	0.326	68	0.009	2006 D
79 ब्राजील	0.754	0.561	25.6	-19	1.005	1	0.414	92	0.010 ^{g,h}	2014 N
79 ग्रेनाडा	0.754
81 बोलिविया और इजुगोविना	0.750	0.650	13.3	6	0.923	4	0.158	34	0.006 ^f	2011/2012 M
82 मेसीडोनिया (पूर्व यूगोस्लाव गणराज्य)	0.748	0.623	16.7	1	0.947	3	0.160	36	0.007 ^f	2011 M
83 अल्जीरिया	0.745	0.854	5	0.429	94
84 आर्मेनिया	0.743	0.674	9.3	15	0.993	1	0.293	61	0.002	2010 D
84 यूक्रेन	0.743	0.690	7.2	18	1.000	1	0.284	55	0.001 ^g	2012 M
86 जॉर्डन	0.741	0.619	16.5	3	0.864	5	0.478	111	0.004	2012 D
87 मेरू	0.740	0.580	21.6	-8	0.959	2	0.385	86	0.043	2012 D
87 थाईलैंड	0.740	0.586	20.8	-5	1.001	1	0.366	79	0.004	2005/2006 M
89 इक्वाडोर	0.739	0.587	20.5	-1	0.976	1	0.391	88	0.015	2013/2014 N
90 चीन	0.738	0.954	2	0.164	37	0.023 ^h	2012 N
91 फिजी	0.736	0.624	15.3	9	0.358	75
92 मंगोलिया	0.735	0.639	13.0	13	1.026	2	0.278	53	0.047 ^f	2010 M
92 सेंट लूसिया	0.735	0.618	16.0	7	0.986	1	0.354	74	0.003 ^h	2012 M
94 जर्मनी	0.730	0.609	16.6	6	0.975	2	0.422	93	0.011	2012 N
95 कोलंबिया	0.727	0.548	24.6	-9	1.004	1	0.393	89	0.032	2010 D
96 डोमिनिका	0.726
97 सुरीनाम	0.725	0.551	24.0	-7	0.972	2	0.448	99	0.033 ^f	2010 M
97 ट्यूनीशिया	0.725	0.562	22.5	-3	0.904	4	0.289	58	0.006	2011/2012 M
99 डोमिनिक गणराज्य	0.722	0.565	21.7	1	0.990	1	0.470	107	0.025	2013 D
99 सेंट व्हिसेंट और ग्रेनेडाईस	0.722
101 टोंगा	0.721	0.969	2	0.659	152
102 लीबिया	0.716	0.950	2	0.167	38	0.005	2007 P
103 बेलीज	0.706	0.546	22.7	-6	0.967	2	0.375	81	0.030	2011 M
104 समोआ	0.704	0.439	97
105 मालदीव	0.701	0.529	24.6	-9	0.937	3	0.312	64	0.008	2009 D
105 उज्बेकिस्तान	0.701	0.590	15.8	10	0.946	3	0.287	57	0.013	2006 M
मध्यम मानव विकास										
107 मालदोवा गणराज्य	0.699	0.628	10.2	21	1.010	1	0.232	46	0.004	2012 M
108 बोल्टाना	0.698	0.433	37.9	-23	0.984	1	0.435	95
109 गैबन	0.697	0.531	23.9	-3	0.923	4	0.542	127	0.073	2012 D
110 वेरुवे	0.693	0.524	24.3	-5	0.966	2	0.464	104
111 फिज	0.691	0.491	29.0	-10	0.884	5	0.565	135	0.016 ⁱ	2014 D
111 तुर्कमेनिस्तान	0.691	0.011	2006 M
113 इंडोनेशिया	0.689	0.563	18.2	9	0.926	3	0.467	105	0.024 ^g	2012 D
114 फलस्तीन राज्य	0.684	0.581	15.1	13	0.867	5	0.005	2014 M
115 वियतनाम	0.683	0.562	17.8	9	1.010	1	0.337	71	0.016 ^g	2013/2014 M

एचडीआई श्रेणी	मानव विकास सूचकांक	असमानता-समायोजित एचडीआई			लैंगिक विकास सूचकांक		लैंगिक असमानता सूचकांक		बहुआयामी निर्धनता सूचकांक	
	मान	मान	सकल हानि	एचडीआई श्रेणी से अंतर ^a	मान	समूह ^b	मान	श्रेणी	मान	वर्ष तथा सर्वे ^c
एचडीआई श्रेणी	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	मान	2006-2015
116 फिलीपींस	0.682	0.556	18.4	8	1.001	1	0.436	96	0.033 ^g	2013 D
117 अल साल्वाडोर	0.680	0.529	22.2	3	0.958	2	0.384	85
118 बोलीविया बहुराष्ट्रीय राज्य	0.674	0.478	29.0	-6	0.934	3	0.446	98	0.097	2008 D
119 दक्षिण अफ्रीका	0.666	0.435	34.7	-12	0.962	2	0.394	90	0.041	2012 N
120 किर्गिस्तान	0.664	0.582	12.3	20	0.967	2	0.394	90	0.008	2014 M
121 इराक	0.649	0.505	22.3	1	0.804	5	0.525	123	0.052	2011 M
122 काबो वर्डे	0.648	0.518	20.1	4
123 मोरक्को	0.647	0.456	29.5	-2	0.826	5	0.494	113	0.069	2011 P
124 निकारागुआ	0.645	0.479	25.8	1	0.961	2	0.462	103	0.088	2011/2012 D
125 ग्वाटेमाला	0.640	0.450	29.6	-2	0.959	2	0.494	113
125 नामीबिया	0.640	0.415	35.2	-13	0.986	1	0.474	108	0.205	2013 D
127 गुयाना	0.638	0.518	18.8	10	0.943	3	0.508	117	0.031	2009 D
127 माइक्रोनेशिया संघीय राज्य	0.638
129 ताजिकिस्तान	0.627	0.532	15.2	16	0.930	3	0.322	65	0.031	2012 D
130 होंडुरस	0.625	0.443	29.2	0	0.942	3	0.461	101	0.098 ^k	2011/2012 D
131 भारत	0.624	0.454	27.2	4	0.819	5	0.530	125	0.282	2005/2006 D
132 भूटान	0.607	0.428	29.4	-3	0.900	5	0.477	110	0.128	2010 M
133 तिमोर लेस्ते	0.605	0.416	31.2	-5	0.858	5	0.322	2009/2010 D
134 मनुआतू	0.597	0.494	17.2	12	0.135	2007 M
135 कोमो	0.592	0.446	24.8	6	0.932	3	0.592	141	0.192	2011/2012 D
135 इक्वेटोरियल गिनी	0.592
137 फिजी	0.588	0.394	33.1	-7
138 लाओ लोकतांत्रिक गणराज्य	0.586	0.427	27.1	1	0.924	4	0.468	106	0.186	2011/2012 M
139 बांग्लादेश	0.579	0.412	28.9	-2	0.927	3	0.520	119	0.188	2014 D
139 घाना	0.579	0.391	32.5	-8	0.899	5	0.547	131	0.147	2014 D
139 जापान	0.579	0.373	35.6	-11	0.924	4	0.526	124	0.264	2013/2014 D
142 साओ तोम और प्रिंसिप	0.574	0.432	24.7	7	0.907	4	0.524	122	0.217	2008/2009 D
143 कंबोडिया	0.563	0.436	22.5	11	0.892	5	0.479	112	0.150	2014 D
144 नेपाल	0.558	0.407	27.0	2	0.925	4	0.497	115	0.116	2014 M
145 म्यांमार	0.556	0.374	80
146 केन्या	0.555	0.391	29.5	-1	0.919	4	0.565	135	0.166	2014 D
147 पाकिस्तान	0.550	0.380	30.9	-2	0.742	5	0.546	130	0.237	2012/2013 D
निम्न मानव विकास										
148 स्वाजीलैंड	0.541	0.361	33.3	-5	0.853	5	0.566	137	0.113	2010 M
149 सीरिया अरब गणराज्य	0.536	0.419	21.8	10	0.851	5	0.554	133	0.028	2009 P
150 अंगोला	0.533	0.336	37.0	-8
151 तंजानिया संसृक्त गणराज्य	0.531	0.396	25.4	7	0.937	3	0.544	129	0.335	2010 D
152 नाइजीरिया	0.527	0.328	37.8	-10	0.847	5	0.279	2013 D
153 कैमरून	0.518	0.348	32.8	-1	0.853	5	0.568	138	0.260	2011 D
154 पापुआ न्यू गिनी	0.516	0.595	143
154 जिंबाब्वे	0.516	0.369	28.5	2	0.927	3	0.540	126	0.128	2014 M
156 सोलोमोन द्वीपसमूह	0.515	0.392	23.8	9
157 मौरिटानिया	0.513	0.347	32.4	1	0.818	5	0.626	147	0.291	2011 M
158 मेडागारस्कर	0.512	0.374	27.0	7	0.948	3	0.420	2008/2009 D
159 रवांडा	0.498	0.339	31.9	1	0.992	1	0.383	84	0.253	2014/2015 D
160 कोमोरोस	0.497	0.270	45.8	-18	0.817	5	0.165	2012 D/M
160 लेसोथो	0.497	0.320	35.6	-6	0.962	2	0.549	132	0.227	2009 D
162 सेनेगल	0.494	0.331	33.1	1	0.886	5	0.521	120	0.278	2014 D
163 हैती	0.493	0.298	39.6	-7	0.593	142	0.242	2012 D
163 सूरीना	0.493	0.341	30.9	6	0.878	5	0.522	121	0.359	2011 D
165 सूडान	0.490	0.839	5	0.575	140	0.290	2010 M
166 टोगो	0.487	0.332	31.9	5	0.841	5	0.556	134	0.242	2013/2014 D
167 बेनिन	0.485	0.304	37.4	-3	0.858	5	0.613	144	0.343	2011/2012 D
168 यमन	0.482	0.320	33.7	0	0.737	5	0.767	159	0.200	2013 D
169 अफगानिस्तान	0.479	0.327	31.8	3	0.609	5	0.667	154	0.293 ^f	2010/2011 M
170 मालावी	0.476	0.328	31.2	5	0.921	4	0.614	145	0.273	2013/2014 M
171 आइवरी कोस्ट	0.474	0.294	37.8	-2	0.814	5	0.672	155	0.307	2011/2012 D
172 जिबूती	0.473	0.310	34.6	3	0.127	2006 M
173 गांबिया	0.452	0.878	5	0.641	148	0.289	2013 D

एचडीआई श्रेणी	मानव विकास सूचकांक	असमानता-समायोजित एचडीआई			लैंगिक विकास सूचकांक		लैंगिक असमानता सूचकांक		बहुआयामी निर्धनता सूचकांक	
	मान	मान	सकल हानि	एचडीआई श्रेणी से अंतर*	मान	समूह	मान	श्रेणी	मान	वर्ष तथा सर्वे
एचडीआई श्रेणी	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2006-2015
174 इथियोपिया	0.448	0.330	26.3	10	0.842	5	0.499	116	0.537	2011 D
175 माली	0.442	0.293	33.7	0	0.786	5	0.689	156	0.456	2012/2013 D
176 कोमो लोकतांत्रिक गणराज्य	0.435	0.297	31.9	3	0.832	5	0.663	153	0.369	2013/2014 D
177 लाइबेरिया	0.427	0.284	33.4	1	0.830	5	0.649	150	0.356	2013 D
178 गिनी-बिसाऊ	0.424	0.257	39.3	-5	0.495	2006 M
179 इरिट्रिया	0.420
179 सिएरा लियोन	0.420	0.262	37.8	-3	0.871	5	0.650	151	0.411	2013 D
181 मोजाम्बिक	0.418	0.280	33.0	3	0.879	5	0.574	139	0.390	2011 D
181 दक्षिण सूडान	0.418	0.551	2010 M
183 गिनी	0.414	0.270	34.8	2	0.784	5	0.425	2012 D/M
184 बुर्की	0.404	0.276	31.5	4	0.919	4	0.474	108	0.442	2010 D
185 बुर्किना फासो	0.402	0.267	33.6	2	0.874	5	0.615	146	0.508	2010 D
186 चाड	0.396	0.238	39.9	-1	0.765	5	0.695	157	0.545	2010 M
187 नाइजर	0.353	0.253	28.3	1	0.732	5	0.695	157	0.584	2012 D
188 मध्य अफ्रीकी गणराज्य	0.352	0.199	43.5	0	0.776	5	0.648	149	0.424	2010 M
अन्य देश या भूभाग										
कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य
मार्शल द्वीपसमूह
मोनाको
नौरू
सैन मारिनो
सोमालिया	0.500	2006 M
तुवालु
मानव विकास सूचकांक समूह										
अति उच्च मानव विकास	0.892	0.793	11.1	—	0.980	—	0.174	—	..	—
उच्च मानव विकास	0.746	0.597	20.0	—	0.958	—	0.291	—	..	—
मध्यम मानव विकास	0.631	0.469	25.7	—	0.871	—	0.491	—	..	—
निम्न मानव विकास	0.497	0.337	32.3	—	0.849	—	0.590	—	..	—
विकासशील देश	0.668	0.499	25.2	—	0.913	—	0.469	—	..	—
क्षेत्र										
अरब राज्य	0.687	0.498	27.5	—	0.856	—	0.535	—	..	—
पूर्व एशिया और प्रशांत	0.720	0.581	19.3	—	0.956	—	0.315	—	..	—
यूरोप और मध्य एशिया	0.756	0.660	12.7	—	0.951	—	0.279	—	..	—
लातीन अमेरिका और कैरिबियाई	0.751	0.575	23.4	—	0.981	—	0.390	—	..	—
दक्षिण एशिया	0.621	0.449	27.7	—	0.822	—	0.520	—	..	—
उप-साहारा अफ्रीका	0.523	0.355	32.2	—	0.877	—	0.572	—	..	—
न्यूनतम विकसित देश	0.508	0.356	30.0	—	0.874	—	0.555	—	..	—
छोटे द्वीपसमूह विकासशील राज्य	0.667	0.500	25.1	—	..	—	0.463	—	..	—
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन	0.887	0.776	12.6	—	0.974	—	0.194	—	..	—
विश्व	0.717	0.557	22.3	—	0.938	—	0.443	—	..	—

नोट

- a सभी देशों के समी संकेतक उपलब्ध नहीं थे, अतः विभिन्न देशों के बीच तुलना करते समय सतर्कता बरती जाए। जहाँ संकेतक उपलब्ध हैं, वहाँ उपलब्ध संकेतकों के भारों को 100 प्रतिशत पूरा करने के लिए समायोजित किया गया है। विवरण के लिए http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf पर तकनीकी नोट 5 देखें।
- b उन देशों पर आधारित जिनके लिए असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक सी गणना की गई है।
- c एचडीआई मानों में लैंगिक समतुल्यता से सर्वथा हटते हुए देशों को पांच समूहों में बांटा गया है।
- d D जनसांख्यिकीय तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणों के, M बहुसांख्यिकी संकेतक समूह सर्वेक्षणों के, P अखिल अरब जनसंख्या और परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों के तथा N राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के आंकड़ों की ओर इंगित करता है (राष्ट्रीय सर्वेक्षणों की सूची के लिए <http://hdr.undp.org/en-faq-page/multidimensional-poverty-index-mpi> देखें)।

- e केवल शहरी क्षेत्रों की ओर संकेत करता है।
- f बाल मृत्यु दर का संकेतक अनुपलब्ध है।
- g पोषण के संकेतक अनुपलब्ध हैं।
- h भूमि के प्रकार का संकेतक अनुपलब्ध है।
- i खाना पकाने के ईंधन का संकेतक अनुपलब्ध है।
- j स्कूल उपस्थिति का संकेतक अनुपलब्ध है।
- k बिजली का संकेतक अनुपलब्ध है।

स्रोत

- कॉलम 1** : यूएनडीइएसए (2015), यूनेस्को इंस्टिट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स (2016), संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (2016), विश्व बैंक (2016b), बैरो एंड ली (2016) तथा आईएमएफ (2016) के आंकड़ों पर आधारित एचडीआईआरओ की गणनाएं।
- कॉलम 2** : तकनीकी नोट 2 (http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf पर उपलब्ध) में दी गई कार्यपद्धति में प्रयुक्त असमानता-समायोजित जीवन प्रत्याशा सूचकांक, असमानता-समायोजित शिक्षा सूचकांक और असमानता-समायोजित आय सूचकांक के मानों के ज्यामितीय औसत के रूप में परिगणित।
- कॉलम 3** : कॉलम 1 और 2 के आंकड़ों पर आधारित गणना।
- कॉलम 4** : कॉलम 2 के आंकड़ों तथा जिन देशों के लिए असमानता-समायोजित एचडीआई की गणना की गई है उनकी पुनर्परिगणित एचडीआई श्रेणियों पर गणना।
- कॉलम 5** : यूएनडीइएसए (2015), यूनेस्को इंस्टिट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स (2016), बैरो एंड ली (2016), विश्व बैंक

(2016b) तथा आईएमएफ (2016) के आंकड़ों पर आधारित एचडीआईआरओ की गणनाएं।

कॉलम 6 : कॉलम 5 के आंकड़ों पर आधारित गणना।

कॉलम 7 : संयुक्त राष्ट्र मातृ मृत्यु दर आकलन समूह (2016), यूएनडीइएसए (2015), आईपीयू (2016), यूनेस्को इंस्टिट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स (2016) और आईएलओ (2016) के आंकड़ों पर आधारित गणनाएं।

कॉलम 8 : कॉलम 7 के आंकड़ों पर आधारित गणना।

कॉलम 9 और 10 : तकनीकी नोट 5 (http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf पर उपलब्ध) में वर्णित पुनरीक्षित कार्यपद्धति का उपयोग करते हुए किए गए कॉलम 10 में सूचीबद्ध विभिन्न घरपरिवार सर्वेक्षणों के शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर में घरपरिवारों के अभावों और वंचनाओं के आंकड़ों पर आधारित एचडीआईआरओ की गणनाएं।

नोट

- 1 फपीए 2014
- 2 संयुक्त राष्ट्र 2015a
- 3 संयुक्त राष्ट्र 2015b
- 4 यूएनडीपी 1990
- 5 संयुक्त राष्ट्र 2015a
- 6 संयुक्त राष्ट्र 2016
- 7 संयुक्त राष्ट्र 2016
- 8 यूनिसेफ 2014
- 9 आईईए 2016
- 10 यूएनएड्स 2016a
- 11 यूएनएचसीआर 2016
- 12 यूएनडीपी 2014
- 13 एसआईडीए 2015
- 14 यूएनडीपी 2015a
- 15 यूएनडीईएसए 2016
- 16 डब्ल्यूएचओ 2011
- 17 यूएनएफपीए 2015
- 18 आईएलजीए 2016
- 19 चार्मीज 2015
- 20 अबादीर 2015
- 21 मिलोनोविक (2016) के आंकड़े का उपयोग करते हुए मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय की गणना
- 22 सोशल प्रोग्रेस इंपीरेटिव की सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स वेबसाइट (www.socialprogressimperative.org/global-index/), 12 दिसंबर 2016 को देखी गई
- 23 सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वेबसाइट (<http://worldhappiness.report>), 12 दिसंबर 2016 को देखी गई
- 24 आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की बेटर लाइफ इंडेक्स वेबसाइट (www.oecdbetterlifeindex.org), 12 दिसंबर 2016 को देखी गई
- 25 सेंटर फॉर भूटान स्टडीज और जीएनएच रिसर्च की ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स वेबसाइट (www.grossnationalhappiness.com/articles/), 12 दिसंबर 2016 को देखी गई
- 26 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ग्लोबल पल्स पहल आरंभ की जिसका उद्देश्य सतत विकास और मानवीय कार्य की सेवा में जन हित में बिग डाटा या बड़े आंकड़ों को काम में लाना था। 2014 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने बिग डाटा पर एक वैश्विक कार्य समूह का गठन किया। सतत विकास आंकड़ों पर सरकारों, कॉरपोरेट, संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, लाभ-निरपेक्ष तथा अकादेमिक हितधारकों के बीच वैश्विक भागीदारी स्थापित की गई। वर्तमान में इसके 150 सदस्य हैं।
- 27 डेमिगुक-कुंट तथा अन्य 2014
- 28 हैरिस और मार्क 2009
- 29 डब्ल्यूएफपी 2016
- 30 विश्व बैंक 2016a
- 31 यूनेस्को 2013
- 32 विश्व बैंक 2015a
- 33 दि इकॉनोमिस्ट 2016
- 34 यूएनडीईएसए 2016
- 35 डब्ल्यूईएफ 2016
- 36 केथिनि तथा अन्य 2015
- 37 कैशिन 2016
- 38 यूएन वूमन 2016
- 39 यूएनडीईएसए 2016
- 40 यूएनडीईएसए 2016
- 41 यूएनएड्स 2016b
- 42 डब्ल्यूएचओ 2016
- 43 दि गार्डियन 2016
- 44 डब्ल्यूएचओ 2016
- 45 विश्व बैंक 2015b
- 46 विश्व बैंक 2015b
- 47 यूएनडीपी 2015b
- 48 डमोस हेल्सिंकी 2016
- 49 संयुक्त राष्ट्र 2013
- 50 यूएन वूमन 2015

- Abadeer, A. 2015.** *Norms and Gender Discrimination in the Arab World*. New York: Palgrave Macmillan.
- Barro, R.J., and J.-W. Lee. 2016.** Dataset of Educational Attainment, February 2016 Revision. www.barrolee.com. Accessed 8 June 2016.
- Cashin, C. 2016.** *Health Financing Policy: The Macroeconomic, Fiscal, and Public Finance Context*. World Bank Studies. Washington, DC. <http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/978-1-4648-0796-1>. Accessed 7 November 2016.
- Cecchini, S., F. Filgueira, R. Martínez and C. Rossel. 2015.** *Towards Universal Social Protection. Latin American Pathways and Policy Tools*. Santiago, Chile: Economic Commission for Latin America and the Caribbean.
- Charmes, J. 2015.** "Time Use Across the World: Findings of a World Compilation of Time Use Surveys." HDRO Occasional Paper. www.hdr.undp.org/sites/default/files/charmes_hdr_2015_final.pdf. Accessed 27 October 2016.
- Demirgüç-Kunt, A., L.F. Klapper, D. Singer and P. Van Oudheusden. 2014.** "The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World." Policy Research Working Paper 7255. World Bank, Washington, DC. <http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf>. Accessed 21 December 2016.
- Demos Helsinki. 2016.** "Thousands to Receive Basic Income in Finland: A Trial That Could Lead to the Greatest Societal Transformation of our Time." Helsinki. www.demoshelsinki.fi/en/2016/08/30/thousands-to-receive-basic-income-in-finland-a-trial-that-could-lead-to-the-greatest-societal-transformation-of-our-time/. Accessed 7 November 2016.
- The Economist. 2016.** "Early Childhood Development: Give Me a Child." 29 October.
- The Guardian. 2016.** "Brazil is 'Badly Losing' the Battle against Zika Virus, Says Health Minister." 26 January. www.theguardian.com/world/2016/jan/26/brazil-zika-virus-health-minister-armed-forces-eradication. Accessed 30 November 2016.
- Harris, R., and W. Marks. 2009.** "Compact Ultrasound for Improving Maternal and Prenatal Care in Low-Resource Settings: Review of Potential Benefits, Implementation Challenges, and Public Health Issues." *Journal of Ultrasound Medicine* 28: 1067–1076.
- IEA (International Energy Agency). 2016.** *Energy and Air Pollution: World Energy Outlook Special Report*. Paris. www.iea.org/publications/freepublications/publication/WorldEnergyOutlookSpecialReport2016EnergyandAirPollution.pdf. Accessed 23 August 2016.
- ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex Association). 2016.** "Sexual Orientation Laws in the World: Criminalisation." Geneva. http://ilga.org/downloads/04_ILGA_WorldMap_ENGLISH_Crime_May2016.pdf. Accessed 26 October 2016.
- ILO (International Labour Organization). 2016.** *Key Indicators of the Labour Market: 9th edition*. Geneva. www.ilo.org/kilm. Accessed 9 June 2016.
- IMF (International Monetary Fund). 2016.** World Economic Outlook database. Washington, DC. www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/. Accessed 10 October 2016.
- IPU (Inter-Parliamentary Union). 2016.** Women in national parliaments. www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm. Accessed 19 July 2016.
- Milanović, B. 2016.** *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization*. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.
- SIDA (Swedish International Development Agency). 2015.** *Women and Land Rights*. Stockholm. www.sida.se/English/contact-us/offices-in-sweden/?epieditmode=true. Accessed 26 October 2016.
- UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS). 2016a.** *AIDS by the Numbers*. Geneva. www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/AIDS-by-the-numbers-2016_en.pdf. Accessed 23 August 2016.
- . 2016b. *Global Aids Update 2016*. Geneva. www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-update-2016_en.pdf. Accessed 25 August 2016.
- UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs). 2015.** *World Population Prospects: The 2015 Revision*. New York. <https://esa.un.org/unpd/wpp/>. Accessed 19 July 2016.
- . 2016. *Global Sustainable Development Report*. [https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2328Global%20Sustainable%20development%20report%202016%20\(final\).pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2328Global%20Sustainable%20development%20report%202016%20(final).pdf). Accessed 1 November 2016.
- UNDP (United Nations Development Programme). 1990.** *Human Development Report 1990: Concept and Measurement of Human Development*. New York. <http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1990>. Accessed 11 October 2016.
- . 2014. *Beyond Geography, Unlocking Human Potential*. Kathmandu. www.hdr.undp.org/sites/default/files/nepal_nhdr_2014-final.pdf. Accessed 26 October 2016.
- . 2015a. *Growth that Works for All: Viet Nam Human Development Report 2015 on Inclusive Growth*. Hanoi. www.hdr.undp.org/sites/default/files/nhdr_2015_e.pdf. Accessed 26 October 2016.
- . 2015b. *Human Development Report 2015. Work for Human Development*. New York. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf. Accessed 11 October 2016.
- UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). 2013.** *Education for All Global Monitoring Report—Girls' Education—The Facts*. Paris.
- UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Institutes for Statistics. 2016.** Data Centre. <http://data.uis.unesco.org>. Accessed 10 June 2016.
- UNFPA (United Nations Population Fund). 2014.** *State of World Population 2014: The Power of 1.8 Billion*. New York. www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/EN-SWOP14-Report_FINAL-web.pdf. Accessed 20 October 2016.
- . 2015. *State of World Population 2015*. www.unfpa.org/migration. Accessed 26 October 2016.
- UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). 2016.** *Global Trends. Forced Displacement in 2015*. Geneva. <https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf>. Accessed 23 August 2016.
- UNICEF (United Nations Children's Fund). 2014.** *Ending Child Marriage: Progress and Prospects*. New York. www.unicef.org/media/files/Child_Marriage_Report_7_17_LR..pdf. Accessed 23 August 2016.
- United Nations. 2013.** "Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression." Note by the Secretary-General. A/68/362. New York. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/464/76/pdf/N1346476.pdf?OpenElement>. Accessed 7 November 2016.

- . **2015a.** *The Millennium Development Goals Report 2015*. New York. [www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20\(July%2011\).pdf](http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%2011).pdf). Accessed 23 August 2016.
- . **2015b.** "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015." New York. www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E. Accessed 11 October 2016.
- . **2016.** *The Sustainable Development Goals Report 2016*. New York. <http://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20Report%202016.pdf>. Accessed 23 August 2016.
- United Nations Statistics Division. 2016.** National Accounts Main Aggregates Database. <http://unstats.un.org/unsd/snaama>. Accessed 15 October 2016.
- UN Maternal Mortality Estimation Group (World Health Organization, United Nations Children's Fund, United Nations Population Fund and World Bank). 2016.** Maternal mortality data. <http://data.unicef.org/topic/maternal-health/maternal-mortality/>. Accessed 28 April 2016.
- UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). 2015.** "World Leaders Agree: We Must Close the Gender Gap: Historic Gathering Boosts Political Commitment for Women's Empowerment at the Highest Levels." Press release, 27 September. New York. www.unwomen.org/en/news/stories/2015/9/press-release-global-leaders-meeting. Accessed 12 December 2016.
- . **2016.** "Facts and Figures: Leadership and Political Participation: Women in Parliaments." www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures. Accessed 22 November 2016.
- WEF (World Economic Forum). 2016.** *The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution*. Geneva. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf. Accessed 25 August 2016.
- WFP (World Food Programme). 2016.** "School Meals." Rome. www.wfp.org/school-meals. Accessed 7 November 2016.
- WHO (World Health Organization). 2011.** *World Report on Disability*. www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/. Accessed 28 November 2016.
- . **2016.** "Zika Strategic Response Plan." Geneva. <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246091/1/WHO-ZIKV-SRF-16.3-eng.pdf>. Accessed 12 December 2016.
- World Bank. 2015a.** "Boosting the Health of Toddlers" Bodies and Brains Brings Multiple Benefits: But Too Often the Wrong Methods Are Used." Washington, DC. www.worldbank.org/en/topic/early-childhooddevelopment/overview. Accessed 7 November 2016.
- . **2015b.** "5 Ways to Reduce the Drivers of Climate Change." Washington, DC. www.worldbank.org/en/news/feature/2015/03/18/5-ways-reduce-drivers-climate-change?cid=CCG_TTccgEN_D_EXT. Accessed 7 November 2016.
- . **2016a.** *Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality*. Washington DC. www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity. Accessed 22 November 2016.
- . **2016b.** World Development Indicators database. Washington, DC. <http://data.worldbank.org>. Accessed 14 October 2016.

एच.डी.आई. देशों तथा श्रेणियों की कुंजी, 2015

अफगानिस्तान	169
अल्बानिया	75
अल्जीरिया	83
एंडोरा	32
अंगोला	150
एंटीगुआ और बरबूडा	62
अर्जेंटीना	45
आर्मेनिया	84
ऑस्ट्रेलिया	2
ऑस्ट्रिया	24
अज़रबैजान	78
बहामाज	58
बहरीन	47
बांग्लादेश	139
बारबाडोस	54
बेलारूस	52
बेल्जियम	22
बेसीज	103
बेनिन	167
भूटान	132
बोलीविया (बहुराष्ट्रीय राज्य)	118
बोस्निया और हर्ज़ेगोविना	81
बोत्स्वाना	108
ब्राजील	79
कनैई दारुस्सलाम	30
बुल्गारिया	56
बुरुकिनो फासो	185
बुरुंडी	184
काबो वेर्डे	122
कंबोडिया	143
कैमरून	153
कनाडा	10
मध्य अफ्रीकी गणराज्य	188
चाड	186
चिली	38
चीन	90
कोलंबिया	95
कोमोरोस	160
कांगो	135
कांगो गणतान्त्रिक गणराज्य	176
कोरटा रिका	66
कोट दिव्वार	171
क्रोएशिया	45
क्यूबा	68
साइप्रस	33
चेक गणराज्य	28
डेनमार्क	5
जिबूती	172
डोमिनिका	96
डोमिनिकन गणराज्य	99
इक्वाडोर	89
मिस्र	111
अल साल्वाडोर	117
इक्वेटोरियल गिनी	135
एरिट्रिया	179
एस्टोनिया	30
इथियोपिया	174
फिजी	91
फिनलैंड	23
फ्रांस	21
गैबन	109
गाबिया	173

जॉर्जिया	70
जर्मनी	4
घाना	139
ग्रीस	29
ग्रेनाडा	79
ग्वाटेमाला	125
गिनी	183
गिनी बिसाऊ	178
गुयाना	127
हैती	163
हॉंडुरास	130
हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.)	12
हंगरी	43
आइसलैंड	9
भारत	131
इंडोनेशिया	113
ईरान (इस्लामी गणराज्य)	69
इराक	121
आयरलैंड	8
इस्राइल	19
इटली	26
जमैका	94
जापान	17
जोर्डन	86
कजाखस्तान	56
केन्या	146
किरिबाती	137
कोरिया (गणराज्य)	18
कुवैत	51
किर्गिस्तान	120
लाओ जनतान्त्रिक गणराज्य	138
लातविया	44
लेबनान	76
लेसोथो	160
लाइबेरिया	177
लीबिया	102
लिब्टेसटीन	15
लिथुआनिया	37
लक्जमबर्ग	20
मैडागास्कर	158
मलावी	170
मलेशिया	59
मालदीव	105
माली	175
माल्टा	33
मॉरिटानिया	157
मॉरिशस	64
मेक्सिको	77
माइक्रोनेशिया (संघीय राज्य)	127
मोल्दोवा (गणराज्य)	107
मंगोलिया	92
मॉन्टीनेग्रो	48
मोरक्को	123
मोजाम्बीक	181
म्यांमार	145
नामीबिया	125
नेपाल	144
नीदरलैंड	7
न्यू जीलैंड	13
निकारागुआ	124
नाइजर	187
नाइजीरिया	152
नॉर्वे	1

ओमान	52
पाकिस्तान	147
पलाऊ	60
फलीस्तीन राज्य	114
पनामा	60
पापुआ न्यू गिनी	154
पेरामे	110
पेरू	87
फिलीपींस	116
पोलैंड	36
पुर्तगाल	41
कतर	33
रोमानिया	50
रूसी संघ	49
रवांडा	159
सेंट किट्स और नेविस	74
सेंट लूसिया	92
सेंट विन्सेन्ट और दि ग्रेनाडाइन	99
समोआ	104
साओ टोम और प्रिन्सीप	142
सऊदी अरब	38
सेनेगल	162
सर्बिया	66
सेशेल्स	63
सिएरा लियोन	179
सिंगापुर	5
स्लोवाकिया	40
स्लोवेनिया	25
सोलोमन द्वीपसमूह	156
दक्षिण अफ्रीका	119
दक्षिण सूडान	181
स्पेन	27
श्रीलंका	73
सूडान	165
सूरीनाम	97
स्वाजीलैंड	148
स्वीडन	14
स्विट्जरलैंड	2
सीरियाई अरब गणराज्य	149
ताजिकिस्तान	129
तंजानिया संयुक्त गणराज्य	151
थाईलैंड	87
मैसीडोनिया (पूर्व यूगोस्लाव गणराज्य)	82
टिमोर-लेस्ट	133
टोंगो	166
टोंगा	101
त्रिनिडाड और टोबागो	65
ट्यूनीशिया	97
तुर्की	71
तुर्कमेनिस्तान	111
यूगांडा	163
यूक्रेन	84
संयुक्त अरब अमीरात	42
यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन)	16
संयुक्त राज्य अमेरिका	10
उरुग्वे	54
उज्बेकिस्तान	105
वनुआतु	134
वेनेजुएला (बोलिवेरियाई गणराज्य)	71
वियतनाम	115
यमन	168
जाम्बिया	139
जिम्बाब्वे	154



संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
वन यूनाइटेड नेशंस प्लाजा
न्यू यॉर्क, एनवाय 10017

www.undp.org

सार्वभौमिकता मानव विकास पद्धति के मूल में है। मानव स्वतंत्रताओं का विस्तार किया ही जाना चाहिए, सभी मनुष्यों के लिए – विश्व के हर एक कोने में कुछ मनुष्यों के लिए नहीं, न ही अधिकांश के लिए, बल्कि सभी के लिए – ताकि वे अभी और भविष्य में अपनी पूर्ण क्षमताओं को साकार कर सकें। यही भावना एजेंडा 2030 और सतत विकास लक्ष्यों में भी निहित है – किसी को भी छोड़ा न जाए। इसलिए मानव विकास हर एक मनुष्य के लिए सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए।

पिछली चौथाई सदी में मानव विकास में प्रभावशाली प्रगति हुई है, जिससे अरबों मानव जीवन समृद्ध हुए हैं। तो भी यह प्रगति असमान रही है, जिसमें समूहों, समुदायों और समाजों को उपेक्षित छोड़ दिया गया है। कुछ लोगों ने केवल आधारभूत मानव विकास हासिल किया है, तो कुछ ने तो वह भी नहीं। विशिष्ट स्थानों और विशिष्ट परिस्थितियों में रह रहे लोगों के बीच अभाव और वंचनाएं अधिक गहरी हैं।

और मानव विकास की राह में ठोस अवरोध बने हुए हैं, जिनमें से कुछ सामाजिक और राजनीतिक पहचानों और संबंधों में गहरे धसे हुए हैं वृ जैसे प्रबल हिंसा, पक्षपातपूर्ण विधि-विधान, बहिष्कारक सामाजिक नियम-कायदे, राजनीतिक भागीदारी में असंतुलन और अवसरों का असमान वितरण।

तथापि मानव विकास का अर्थ मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने से कहीं अधिक है। इसमें वाणी और स्वायत्तता भी शामिल हैं, जो गतिशील विश्व में और जीवन की बदलती हुई परिस्थितियों के दौरान महत्वपूर्ण हैं। मानव विकास का अर्थ है कर्तव्य, आत्म-निर्धारण और चयन करने तथा परिणामों को गढ़ने की स्वतंत्रता।

"मानवता ने विगत 25 वर्षों में जो हासिल किया है, उससे उम्मीद बंधती है कि बुनियादी बदलाव संभव है। हमने जो हासिल किया है उसके आधार पर आगे का निर्माण कर सकते हैं, चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए हम नई संभावनाओं का दोहन कर सकते हैं, पहले जो अप्राप्य जान पड़ता था उसे प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदों को साकार करना हमारी पहचान है।"

—हेलेन क्लार्क, प्रशासक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

"हर एक के लिए मानव विकास ऐसी प्रतिबद्धता है जो हमारे देश से भी आगे जाती है और हम चाहते हैं कि हमारा काम दूसरे राष्ट्रों के नागरिकों के जीवन को भी प्रभावित और समृद्ध करे।"

—हुआन मैनुअल सांतोस, कोलंबिया के राष्ट्रपति और 2016 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता

"प्रतिदिन और प्रतिरात, हम सभी की जिम्मेदारी है कि सतत विकास को हम अपने कार्य का मार्गदर्शक सिद्धांत बनाएं – व्यवसाय और समाज के जिम्मेदार राजनीतिज्ञ और निर्णयकर्ता होने के नाते, अपने भविष्य में सच्ची रूचि रखने वाले व्यक्तियों के नाते।"

—डॉ. एंजेल मर्केल, जर्मनी संघीय गणराज्य की चांसलर

"अधिक प्रभावी नीतियों और हस्तक्षेपों की रूपरेखा बनाने और उसे क्रियान्वित करने की दिशा में, और साथ ही सर्वाधिक प्रभाव की दृष्टि से अल्प संसाधनों को बेहतर लक्ष्यबद्ध करने की दिशा में भी, गरीबी और अभावों की अधिक स्पष्ट तस्वीर हासिल करना पहला कदम है।"

—मेलिंडा गेट्स, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह-अध्यक्ष

"मानव विकास सार्वभौमिकता को प्रतिबिंबित करता है वृ हर एक जीवन का महत्व है और हर एक जीवन बराबर से मूल्यवान है। हर एक मानव जीवन को समृद्ध करने के लिए मानव विकास को सतत और सातत्यपूर्ण होना ही होगा ताकि हम सब अपने जीवन की पूर्ण सामर्थ्य को साकार कर सकें।"

—सलीम जहां, रिपोर्ट के अग्रणी लेखक